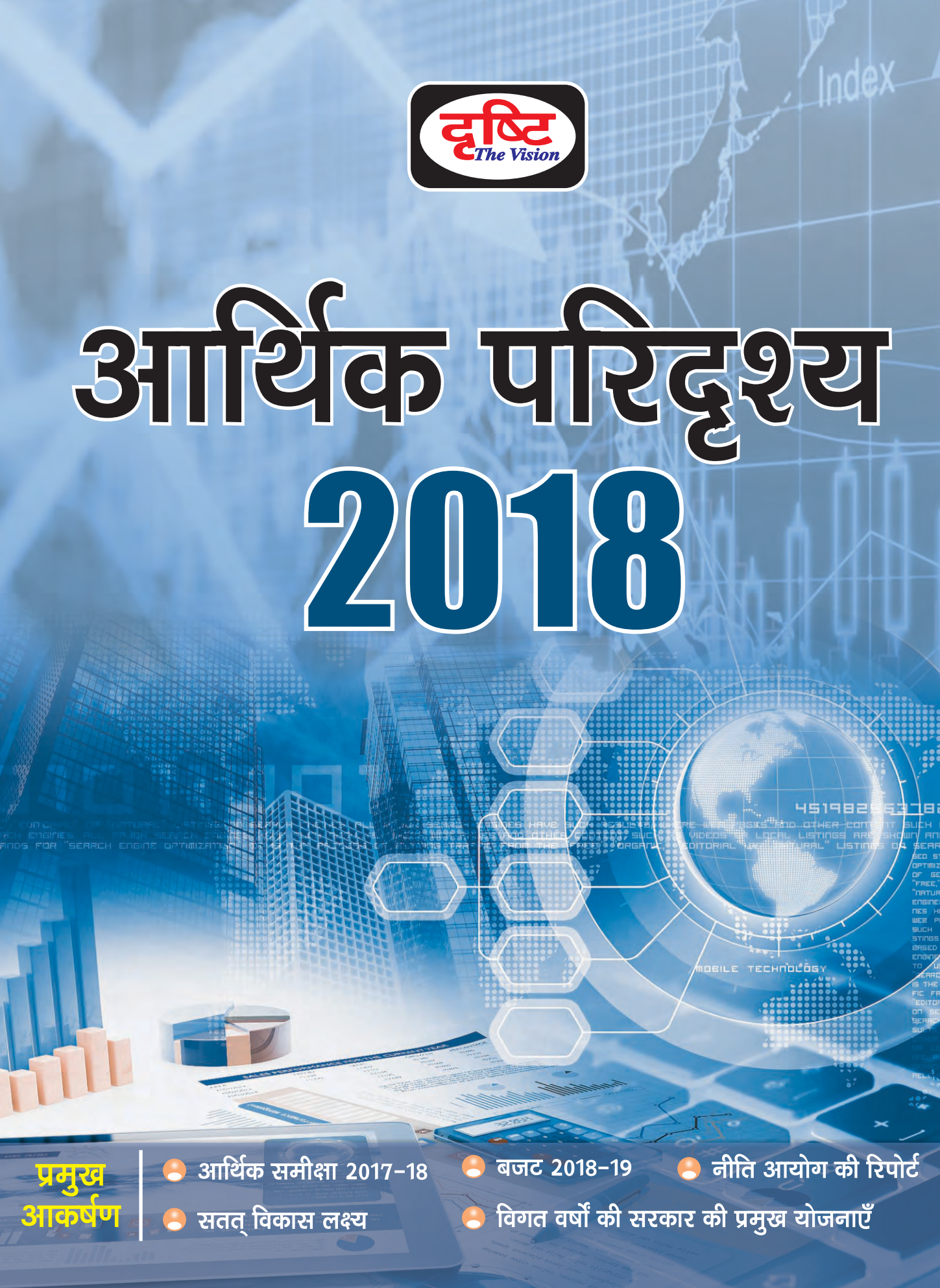


आर्थिक परिदृश्य 2018

प्रमुख आकर्षण

- आर्थिक समीक्षा 2017–18
- सतत् विकास लक्ष्य
- बजट 2018–19
- विगत वर्षों की सरकार की प्रमुख योजनाएँ
- नीति आयोग की रिपोर्ट

दृष्टि The Vision

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
Distance Learning Programme

उपलब्ध

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे दृष्टि संस्थान द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री, विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है जो किसी कारण से दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षा की पाठ्य-सामग्री, नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएगी।

UPSC के लिये

यह पाठ्य-सामग्री सिविल सेवा परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) एवं परीक्षोपयोगी बनाया गया है।

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(27 + 3 Booklets) (₹12,000/-)

सामान्य अध्ययन
(मुख्य परीक्षा)
(23 Booklets) (₹10,000/-)

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(27 + 3 + 8 Booklets) (₹15,000/-)

हिन्दी साहित्य
(वैकल्पिक विषय) (₹6,000/-)

दर्शनशास्त्र
(वैकल्पिक विषय) (₹5,000/-)

इतिहास
(वैकल्पिक विषय) (₹7,000/-)

MP PSC के लिये

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (राज्य सेवा) परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप हमने डी.एल.पी. प्रोग्राम तैयार किया है। इसमें मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार की प्रामाणिक रिपोर्टों तथा सामान्य अध्ययन की जटिल एवं बिखरी पाठ्य-सामग्रियों का इस प्रकार से संकलन किया गया है जिससे अभ्यर्थियों की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ हो जाती है। यह पाठ्य-सामग्री नि:संदेह आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगी।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत
कुल 36 बुकलेट्स दी जाएंगी

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 Booklets) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(28 Booklets) (₹10,000/-)

सीसैट
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(8 Booklets) (₹2,500/-)

मध्य प्रदेश डी.एल.पी. की सफलता के पश्चात्
तीन नए राज्यों (राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड) की डी.एल.पी. की शुरुआत

आर्थिक परिदृश्य 2018

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website:
www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail :
booksteam@groupdrishti.com

प्रथम संस्करण- मार्च 2018

मूल्य : ₹ 260

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,
(A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © **कॉपीराइट :** दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द...

प्रिय पाठको,

आपके समक्ष 'आर्थिक परिदृश्य-2018' प्रस्तुत करते हुए एक बार फिर हमें हार्दिक खुशी हो रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी 'दृष्टि पब्लिकेशन्स' द्वारा 'आर्थिक परिदृश्य-2016' और 'आर्थिक परिदृश्य-2017' का प्रकाशन किया जा चुका है। आपसे प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित विभिन्न एकदिवसीय परीक्षाओं में इन पुस्तकों ने महती भूमिका निभाई है। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं और प्रबल मांगों को ध्यान में रखकर ही यह नवीन पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि पूर्व की तरह यह भी अभ्यर्थियों की सफलता में मील का पत्थर साबित होगी।

आप इस बात से भलीभाँति परिचित हैं कि सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में 'भारतीय अर्थव्यवस्था' खंड का महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक तरफ प्रारंभिक परीक्षा में जहाँ यह खंड सफलता की कुंजी के रूप में स्थापित है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य परीक्षा में भी इसके बिना अच्छे अंक प्राप्त करना असंभव है। इसका मुख्य कारण यह है कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न अवधारणाओं एवं तथ्यों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध सामान्य अध्ययन के अन्य विषयों, जैसे- सामाजिक न्याय एवं कल्याण से संबंधित मुद्दों, आर्थिक और सामाजिक विकास, राजव्यवस्था, गवर्नेन्स, समसामयिकी इत्यादि से है। इसके साथ लगभग प्रतिवर्ष निबंध खंड में कम-से-कम एक निबंध आर्थिक मुद्दे से संबंधित होता है। अब, यदि सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यस्था खंड का गहन विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इस खंड में 'आर्थिक समीक्षा' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सिविल सेवा (प्रारंभिक + मुख्य) परीक्षा के प्रश्नों का झुकाव समसामयिक मुद्दों की ओर अधिक होता है, यह बात भारतीय अर्थव्यवस्था खंड पर भी लागू होती है। ऐसे में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में इस खंड से संबंधित प्रश्नों के साथ न्याय 'आर्थिक समीक्षा' के अध्ययन के बिना नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत पुस्तक मुख्य रूप से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'आर्थिक समीक्षा 2017-18' का सार है। इसमें 'आर्थिक समीक्षा 2017-18' के खंड-I एवं खंड-II का अध्यायवार संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण अत्यंत सरल, बोधगम्य, रुचिकर एवं प्रवाहमय भाषा में किया गया है। इस पुस्तक में आम बजट 2018-19 की भी बिंदुवार प्रस्तुति की गई है। आम बजट 2018-19 के अंतर्गत विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि कृषि, अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे आदि के विकास हेतु किये जाने वाले आवंटन एवं रणनीतियों का प्रस्तुतीकरण किया गया है। इसमें 'आर्थिक समीक्षा 2017-18' में प्रस्तुत की गई भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थितियों, विद्यमान चुनौतियों, भावी संभावनाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों की विगत वर्षों की उपलब्धियों एवं परिणामों का विश्लेषण भी किया गया है।

इस पुस्तक में यूएनडीपी द्वारा वर्ष 2030 तक प्राप्त करने वाले सतत विकास लक्ष्यों का बिंदुवार समावेश किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए भविष्य की रणनीतियों को 'नीति आयोग-तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा' के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ नीति आयोग द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान नए भारत के निर्माण हेतु किये गए महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों और पहलों के संक्षिप्त वर्णन को शामिल किया गया है। इसके अलावा इस पुस्तक में पिछले तीन-चार वर्षों की प्रमुख सरकारी योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है, जो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिये बेहद उपयोगी हैं। चूँकि आर्थिक समीक्षा को समझना एक जटिल कार्य है, इसीलिये विषय-वस्तु की जटिलता को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सरल एवं सहज भाषा के साथ ग्राफिक्स, चार्ट, बॉक्स आदि के माध्यम से सूचनाओं को दर्शाया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी संकलित किये गए हैं जो आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिये अत्यंत उपयोगी साबित होंगे।

मुझे भरोसा है कि पुस्तक का यह संस्करण आपके लिये अति उपयोगी सिद्ध होगा। मेरा निवेदन है कि आप इसे सिर्फ पाठक के रूप में न पढ़ें, बल्कि आलोचक की नज़र से भी पढ़ें। **अगर आपको इसमें कोई भी कमी दिखे तो आप अपना सुझाव बेझिझक '8130392355' नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज दें।** आपकी टिप्पणियों के आधार पर हम पुस्तक के आगामी संस्करणों को और बेहतर बना सकेंगे।

साभार,
प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

http://t.me/Md_Ebooks

अनुक्रम

खंड–1

आर्थिक सर्वेक्षण (2017–18): सार तथा विश्लेषण 1-158

भारतीय अर्थव्यवस्था पर दस नए तथ्य 3

1. अर्थव्यवस्था की स्थिति : विश्लेषणात्मक सिंहावलोकन और नीतिगत संभावनाएँ 7
2. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नूतन प्रबोधक एवं संक्षिप्त विवेचन 19
3. निवेश और बचत में गिरावट और स्थिति में सुधार : भारत के संबंध में विभिन्न देशों का अनुभव 25
4. राजकोषीय संघवाद और जवाबदेही में समन्वय : क्या इसमें निम्न संतुलन अवरोध है? 31
5. क्या विकास में विलंबित अभिसृति एक बाधा बन जाती है? क्या भारत इससे बच पाएगा? 37
6. जलवायु, जलवायु परिवर्तन और कृषि 43
7. कन्या नहीं, पुत्र चाहिये : क्या विकास ही इस समस्या का समाधान है? 52
8. भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का रूपांतरण 61
9. व्यवसाय करने को आसान बनाने का अगला मोर्चा : समय से न्याय 68

खंड–2

10. 2017-18 में भारत के आर्थिक प्रदर्शन का सिंहावलोकन 75
11. राजकोषीय घटनाक्रम की समीक्षा 89
12. मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता 93
13. कीमतें और मुद्रास्फीति 97
14. धारणीय विकास, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन 102
15. वैदेशिक क्षेत्र 111
16. कृषि एवं खाद्य प्रबंधन 122
17. उद्योग और अवसंरचना 132
18. सेवा क्षेत्र 149
19. सामाजिक अवसंरचना, रोज़गार और मानव विकास 158

खंड–3

बजट 2018–2019 169-175

खंड–4

नीति आयोग की रिपोर्ट 176-191

खंड–5

सतत विकास लक्ष्य 192-206

खंड–6

प्रमुख योजनाएँ 207-268

खंड-1 & 2

आर्थिक सर्वेक्षण

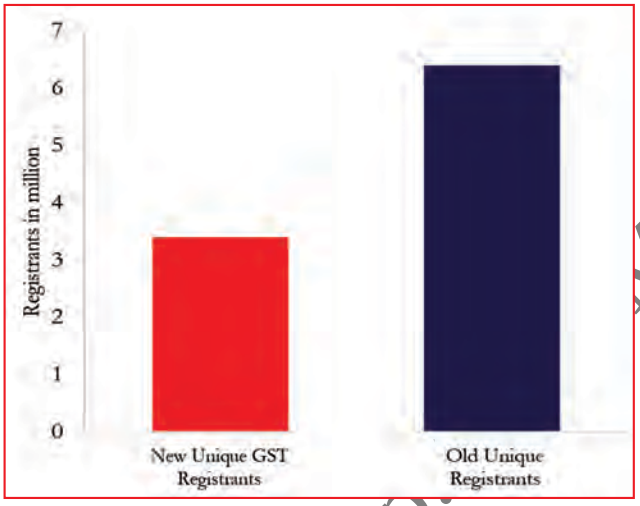
(2017–18)

सार तथा विश्लेषण

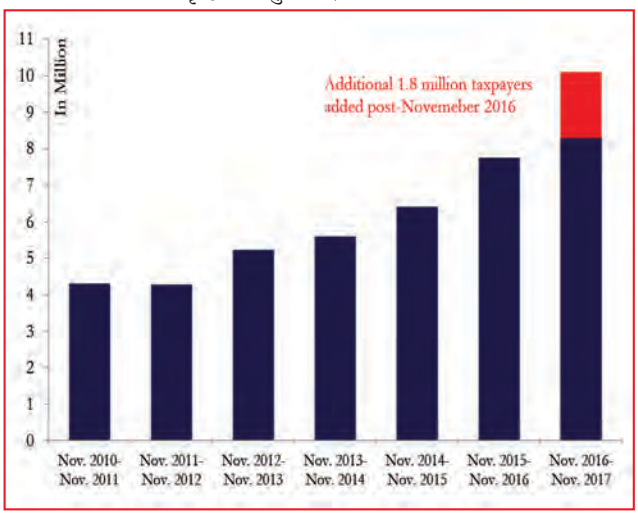
भारतीय अर्थव्यवस्था पर दस नए तथ्य
(Ten New Facts on the Indian Economy)

पंजीकृत अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करदाताओं में भारी वृद्धि हुई है। (There has been a large increase in registered indirect and direct taxpayers.)

- भारत में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के पश्चात् विशिष्ट अप्रत्यक्ष करदाताओं में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

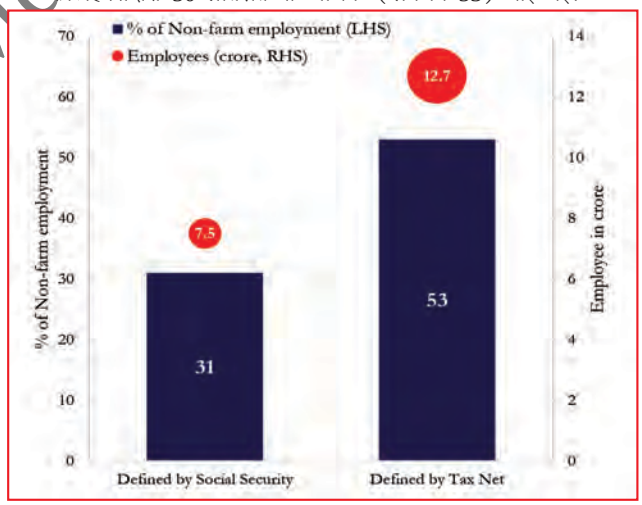


- व्यक्तिगत आयकर फाइल करने वाले व्यक्तियों में नवंबर 2016 की तुलना में नवंबर 2017 में 1.8 मिलियन की वृद्धि हुई है जो कि पिछले वर्षों में हो रही वृद्धि की तुलना में अधिक है।



औपचारिक कृषितर भुगतान चिट्ठा विश्वास से कहीं ज़्यादा है। (Formal non-agricultural payroll is much greater than believed.)

- भारत का औपचारिक क्षेत्र विशेषकर औपचारिक गैर-कृषि पे-रोल को वर्तमान अनुमान की तुलना में बहुत अधिक पाया गया है।
- यह स्पष्ट हुआ है कि जब सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों जैसे कि ईपीएफओ/ईएसआईसी के संदर्भ में औपचारिकता को परिभाषित किया गया तब औपचारिक क्षेत्र से जुड़े पे-रोल को गैर-कृषि श्रम बल का 30 प्रतिशत से अधिक (31 प्रतिशत) पाया गया।
- जब औपचारिकता को जीएसटी दायरे का हिस्सा होने की दृष्टि से परिभाषित किया गया, तब इस तरह के औपचारिक क्षेत्र संबंधी पे-रोल की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक (लगभग 53) पाई गई।



राज्यों की समृद्धि उनके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय व्यापार से सह-संबंधित होती है। (States' prosperity is correlated with their international and inter-state trade.)

- राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात से जुड़े आँकड़ों के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि राज्य के निर्यात प्रदर्शन और राज्यों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर के बीच मज़बूत आपसी जुड़ाव है। वैसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय निर्यात करते हैं और अन्य राज्यों के साथ व्यापार करते हैं, वे अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध पाए गए हैं। इस तरह का आपसी जुड़ाव खुशहाली और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच कहीं अधिक पाया गया है।

http://t.me/Upsc_Civil_Ebooks

1 अर्थव्यवस्था की स्थिति : विश्लेषणात्मक सिंहावलोकन और नीतिगत संभावनाएँ (State of the Economy : An Analytical Overview and Outlook for Policy)

"जो अवश्यंभावी है, वह तो कभी होता नहीं,
होता हमेशा वही है जो कभी सोचा नहीं।"

–जॉन मेनर्ड कीन्ज

*वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुछ बड़े सुधार किये गए। माल और सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि को लागू किया गया और दीर्घकाल से बनी हुई दोहरी तुलन पत्र (टीबीएस) की समस्या का समाधान दृढ़तापूर्वक किया गया, जिसमें बड़ी तनावग्रस्त कंपनियों को नई भारतीय दिवालियापन संहिता के अधीन समाधान करने के लिये संदेश दिया गया और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मज़बूत करने के लिये बड़ा पुनर्पूंजीकरण पैकेज लागू किया गया। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.75 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7-7.5 प्रतिशत तक बढ़नी चाहिये, जिससे विश्व की सर्वाधिक तेज़ गति से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का पुनर्स्थापन होगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कई कार्य हैं- जीएसटी का पूर्णत: स्थिरीकरण, टीबीएस के कार्यों का पूरा किया जाना, एयर इंडिया का निजीकरण और वृहत् आर्थिक स्थायित्व की चुनौतियों का समाधान। दीर्घकालिक 'विकास' की समस्या को दूर करने हेतु ध्यान देने योग्य यह है कि टीबीएस के कार्यों में अलाभकारी बैंकों को कम करने और बड़े स्तर पर निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिये अतिरिक्त सुधार की आवश्यकता है। जीएसटी परिषद् अन्य अनेक नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिये सहकारी संघवाद की एक मॉडल प्रौद्योगिकी की पेशकश करती है। मध्यावधि में, तीन नीतिगत चुनौतियाँ मौजूद हैं, यथा- **रोज़गार:** युवाओं, और बढ़ते कार्यबल, विशेषकर महिलाओं के लिये पर्याप्त रोज़गार उपलब्ध कराना। **शिक्षा:** शिक्षित और स्वस्थ्य श्रमबल का सृजन करना। **कृषि:** कृषि क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण करते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। संक्षेप में, दो संधारणीय कारकों–निजी निवेश और निर्यात के बल पर त्वरित आर्थिक वृद्धि के लिये भारत अपने माहौल के सुधार को जारी रखे।*

सिंहावलोकन : अल्पावधिक संदर्भ में (Overview : Short Term)

- माल और सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया। जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और उन्हें कम करने तथा अनुपालन के बोझ को घटाने के लिये तत्काल कार्रवाई की गई।
- दोहरे तुलन पत्र (टीबीएस) की चुनौती, जो निश्चित रूप से भारत की विकास संभावनाओं में सेंध लगा रही बाध्यकारी अड़चन है, का समाधान करने के लिये निर्णायक कार्रवाई की गई। टीबीएस के चार प्रमुख घटकों–पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार में पहचान के घटक को और आगे बढ़ाया गया जबकि अन्य दो घटकों का समाधान करने के लिये बड़े उपाय किये गए। नई भारतीय दिवालियापन संहिता में एक ऐसे समाधान तंत्र की व्यवस्था की गई है जिससे कॉर्पोरेटों को अपने तुलन पत्र ठीक करने तथा अपने ऋणों को कम करने में मदद मिलेगी और एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपाय के रूप में सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलन पत्रों को मज़बूत बनाने के लिये एक बड़े पुनर्पूंजीकरण पैकेज (जीडीपी का लगभग 1.2 प्रतिशत) की घोषणा की है। जैसे-जैसे ये दो सुधार अपनी पकड़ मज़बूत करेंगे, वैसे-वैसे फर्में आखिरकार निवेश करना शुरू कर सकेंगी और बैंक उन्हें अवसंरचना एवं विनिर्माण के महत्त्वपूर्ण व भारग्रस्त क्षेत्रों में उधार दे सकेंगे।
- इस वर्ष वृहत् आर्थिक घटनाक्रम काफी परिवर्तनशील रहा है। पहली छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थायी तौर पर 'वियोजित' (Decoupled) हो गई, जिसके चलते मज़बूत वृहत् आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के साथ प्रमुख देशों के बीच दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश होने के बावजूद, इसकी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर में गिरावट हो गई जबकि शेष विश्व की संवृद्धि दर बढ़ती रही। इसका कारण ऐसी कार्रवाइयों और विकास कार्यों में निहित था जिन्होंने अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया, जैसे- नोटबंदी, नए माल और सेवाकर में शुरुआती मुश्किलें, ऊँची और बढ़ती वास्तविक ब्याज दरें, टीबीएस चुनौती का गहन प्रभाव और कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज़ी से हुई गिरावट जिससे कृषि आय पर प्रतिकूल असर पड़ा।
- वर्ष के उत्तरार्ध में, जैसे-जैसे इन धक्कों का असर कम होना शुरू हुआ, वास्तविक अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के उत्साहवर्द्धक संकेत देखे गए, सुधारात्मक कार्रवाई की गई, और साथ-साथ चलती वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया ने निर्यातों को बढ़ावा दिया। कारोबार के माहौल में सुधार लाने के लिये की गई संचयी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप, भारत विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 30 स्थान ऊपर बढ़ आया, जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) तंत्र को उदार बनाने के लिये की गई ऐसी ही कार्रवाई के कारण आगम में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- राजकोषीय घाटे, चालू खाता और मुद्रास्फीति उम्मीद से अधिक बनी हुई थी, भले ही अभी खतरनाक स्तर तक नहीं पहुँची थी, लेकिन यह चिंता का विषय अवश्य है।

http://t.me/Md_Ebooks

अभ्यास प्रश्न

1. आर्थिक समीक्षा 2017-18 में वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत किन महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को महत्ता प्रदान की गई है।
   1. जीएसटी का पूर्णत: स्थिरीकरण
   2. दोहरे तुलन पत्र की समस्या का समाधान
   3. एयर इंडिया का निजीकरण
   4. वृहत-आर्थिक स्थायित्व की चुनौतियों का समाधान

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1
   (c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

2. भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख निम्नलिखित में से कौन-कौन सी नीतिगत चुनौतियाँ मौजूद हैं?
   1. युवाओं और बढ़ते कार्यबल विशेषकर महिलाओं हेतु रोज़गार के अवसरों का सृजन करना।
   2. शिक्षित एवं स्वस्थ श्रमबल का सृजन करना।
   3. कृषि क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण करते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ाना।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 3
   (c) 1, 2 और 3
   (d) इनमें से कोई नहीं

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थायी रूप से नियोजित (Decoupled) हो गई, जिसके कारण संवृद्धि दर में कुछ गिरावट हुई है। इसके प्रमुख कारण थे-
   1. विमुद्रीकरण
   2. माल एवं सेवा कर
   3. उच्च वास्तविक ब्याज दरें
   4. दोहरे तुलन पत्र की समस्या
   5. खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4
   (c) केवल 1, 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि वर्ष 2016 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में लगभग 3.6 प्रतिशत हो गई है।
   2. वैश्विक संवृद्धि दर 2000 के दशक की संवृद्धि दर की तुलना में काफी अधिक है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

5. नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा किये गए विमुद्रीकरण के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित था/थे?
   1. अर्थव्यवस्था में औपचारिकीकरण को बढ़ाना
   2. अधिकाधिक भारतीयों को आय कर जाल में लाना
   3. काले धन के संग्रहण को कम करना
   4. अर्थव्यवस्था में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना
   5. अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कम करना

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 2 और 3
   (b) केवल 1, 2 और 5
   (c) केवल 1, 2, 3 और 4
   (d) 1, 2, 3, 4 और 5

6. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. वित्तीय वर्ष 2017-18 में किये गए व्यापक आर्थिक सुधार के चलते वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.75 प्रतिशत रही है।
   2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर लगभग 7-7.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

7. सहकारी संघवाद प्रौद्योगिकी का उपयोग कर राज्यों की किन-किन संरचनात्मक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है?
   1. विखंडित एवं अक्षम विद्युत बाज़ारों को एकीकृत करने
   2. अंतर-राज्यीय जल संबंधी विवादों का निपटान करने
   3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को क्रियान्वित करने
   4. वायु प्रदूषण का समाधान करने

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 2 और 3 (b) केवल 2
   (c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

8. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. भारत ने सहयोगी संघवाद की रचना के रूप में माल एवं सेवा कर परिषद् का अत्यंत कारगर संस्थागत तंत्र बनाया है।
   2. आर्थिक और समाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिये सहकारी संघवाद राज्यों के अपने प्रयासों का एक विकल्प नहीं है अपितु महत्त्वपूर्ण पूरक है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरमाला

1. (d)	2. (c)	3. (c)	4. (a)	5. (c)
6. (c)	7. (d)	8. (c)		

http://t.me/Md_Ebooks

2 माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नूतन प्रबोधक एवं संक्षिप्त विवेचन (A New, Exciting Bird's-Eye View of the Indian Economy Through the GST)

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू किये जाने के पश्चात् अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा अनेक करदाताओं ने स्वेच्छा से जीएसटी को अपनाया है, जिनमें विशेष रूप से ऐसे लघु उद्यम शामिल हैं जो बड़े उद्यमों से क्रय करते हैं तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना चाहते हैं। राज्यों के बीच जीएसटी आधार का वितरण उनकी अर्थव्यवस्था के आकार से मज़बूती से जुड़ा है जिससे प्रमुख उत्पादक राज्यों का यह डर समाप्त हो गया है कि नई प्रणाली को अपनाने से उनके कर संग्रहण में कमी आएगी। राज्यों द्वारा किये जा रहे अंतर्राष्ट्रीय निर्यात से संबंधित नए आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि निर्यात आँकड़ों तथा राज्य के लोगों के जीवन स्तर के बीच एक मज़बूत सह-संबंध विद्यमान है। भारत का आंतरिक व्यापार जीडीपी का लगभग 60 प्रतिशत है जो अन्य बड़े देशों के आंतरिक व्यापार को देखते हुए पर्याप्त अनुकूल है। भारत का औपचारिक क्षेत्र, विशेषकर औपचारिक रूप से कृषि से भिन्न क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों में पे-रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या मौजूदा अनुमान की तुलना में पर्याप्त व्यापक है। सामाजिक सुरक्षा उपबंधों के संदर्भ में निर्धारित की गई औपचारिकताओं से यह अनुमान प्राप्त होता है कि औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारी गैर-कृषि क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों का लगभग 31 प्रतिशत है। औपचारिक क्षेत्र के जीएसटी के ढाँचे में शामिल होने के संदर्भ में यह ज्ञात होता है कि इसमें औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे वैतनिक कर्मचारियों का हिस्सा 53 प्रतिशत है।

परिचय (Introduction)

माल तथा सेवा कर (जीएसटी) सरकार द्वारा की गई एक व्यापक व्यवस्था है। जीएसटी को अनेक कारणों से व्यापक जनसमर्थन मिला है जो विशेषकर एक भारतीय बाज़ार सृजित करने की इसकी क्षमता, कर आधार को विस्तार प्रदान करने तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में इसकी सक्षमता के कारण है। जीएसटी का एक अन्य लाभ यह है कि इससे सूचना का एक बड़ा निक्षेपागार (Repository) सृजित होगा जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को समझने में हमारी सोच को विस्तार मिलेगा तथा उसमें निश्चित रूप से बदलाव आएगा।

जीएसटी से प्राप्त आँकड़ों से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ अधिक कठिन तथा बुनियादी तथ्यों को समझने में मदद मिल सकती है। प्राप्त नए निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-

- अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अनेक करदाताओं ने जीएसटी को स्वेच्छा से अपनाया है जिनमें विशेष रूप से ऐसे लघु उद्यम शामिल हैं जो बड़े उद्यमों से क्रय करते हैं तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना चाहते हैं।
- राज्यों के बीच जीएसटी आधार का संवितरण उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से मज़बूती से जुड़ा है जिससे प्रमुख उत्पादकों का यह डर समाप्त हो गया है कि नई प्रणाली को अपनाने से उनके कर संग्रहण में कमी आएगी।
- राज्यों के द्वारा किये जा रहे अंतर्राष्ट्रीय निर्यात से संबंधित नए आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि निर्यात आँकड़ों तथा राज्य के लोगों के जीवन स्तर के बीच एक मज़बूत सह-संबंध विद्यमान है।
- भारत का निर्यात इस संदर्भ में असामान्य है कि अन्य तुलनीय देशों से हमारे देश में सर्वाधिक बड़ी श्रेणी के प्रतिष्ठानों की निर्यात में भागीदारी काफी कम है।
- आंतरिक व्यापार जीडीपी का लगभग 60 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष की समीक्षा में लगाए गए अनुमान से भी अधिक है तथा अन्य बड़े देशों के आंतरिक व्यापार को देखते हुए पर्याप्त अनुकूल है।
- भारत में, विशेषकर औपचारिक रूप से कृषि से भिन्न क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों में पे-रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या मौजूदा अनुमान की तुलना से काफी ज़्यादा है। सामाजिक सुरक्षा उपबंधों के संदर्भ में निर्धारित की गई औपचारिकताओं से यह अनुमान प्राप्त होता है कि औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारी गैर-कृषि क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के लगभग 31 प्रतिशत हैं। औपचारिक क्षेत्र का जीएसटी के ढाँचे में शामिल होने के संदर्भ में यह ज्ञात होता है कि औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों का इसमें योगदान 53 प्रतिशत है।
- इसी प्रकार, औपचारिक क्षेत्र का आकार (यहाँ या तो सामाजिक सुरक्षा या जीएसटी नेट में शामिल के रूप में परिभाषित) निजी गैर-कृषि क्षेत्र में कुल फर्मों की संख्या का 13 प्रतिशत किंतु उनके कुल टर्नओवर का 93 प्रतिशत है।

करदाता *(Taxpayers)*

- दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार जीएसटी में 9.8 मिलियन नाम पंजीकृत थे जिनकी संख्या पुरानी प्रणाली के तहत पंजीकृत कुल अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या से मामूली अधिक है। किंतु ये दोनों आँकड़े तुलनीय नहीं हैं। पुरानी प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत करदाता इस संदर्भ में एक समान नहीं थे क्योंकि वे अनेक करों के तहत पंजीकृत करदाता थे। करदाताओं के दो और तीन बार गिने गए आधार को समायोजित करते हुए जीएसटी से अद्वितीय अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है जो कुल मिलाकर 3.4 मिलियन है।

http://t.me/Md_EBooks

3 निवेश और बचत में गिरावट और स्थिति में सुधार : भारत के संबंध में विभिन्न देशों का अनुभव (Investment and Saving Slowdowns and Recoveries : Cross-Country Insights for India)

"जितना निवेश होगा उतना ही लाभ होगा।"

-हिमैन मिंस्की

2000 के दशक के मध्य में भारत में निवेश और बचत दरों के अभूतपूर्व ऐतिहासिक उच्च स्तरों पर पहुँचने के बाद, इनमें उतनी ही तीव्रता के साथ क्रमिक गिरावट (Gradual Decline) भी आई है। निवेश और बचत में गिरावट की यह वर्तमान प्रवृत्ति अभी तक जारी है। एक निष्कर्ष यह है कि निवेश में गिरावट का संवृद्धि पर प्रभाव पड़ता है परंतु यह बचत को भी प्रभावित करे, आवश्यक नहीं है। दूसरा यह है कि निवेश में गिरावट से स्थिति में सुधार की गति धीमी रहती है। भारत में गिरावट की प्रवृत्ति तुलन पत्र (Balance Sheet) की समस्या से भी जुड़ी हुई है। संवृद्धि पर प्रभाव को अधिक स्थायी बनने से रोकने के लिये नीतिगत निष्कर्ष निवेश की स्थिति में सुधार की तात्कालिक प्राथमिकता है जैसा कि सरकार ने, अशोधनीय ऋणों के समाधान और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुन:पूंजीकरण की योजना के माध्यम से करना चाहा है।

परिचय (Introduction)

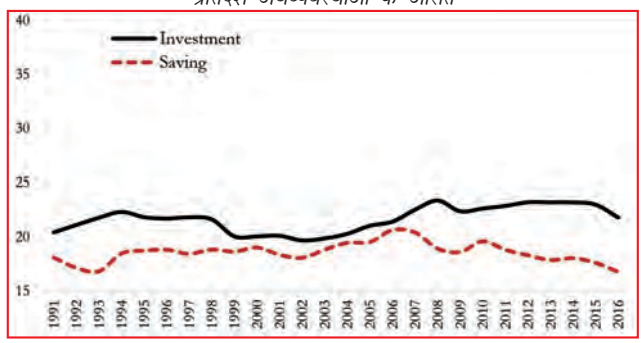
- वर्ष 2010 से, भारत की संवृद्धि विषयक चर्चाएँ इस एक सरल प्रश्न पर केंद्रित रही हैं- कितनी जल्दी अर्थव्यवस्था पुन: 8-10 प्रतिशत संवृद्धि पर लौट आएगी? हालिया वर्षों में सरकार द्वारा क्रियान्वित किये गए सभी संरचनात्मक सुधारों को देखते हुए लगता है कि यह शीघ्र ही होने वाला भी है।
- इन प्रत्याशाओं में यह दृढ़ विश्वास निहित है कि घरेलू बचत और निवेश में शीघ्र ही तेज़ी आने वाली है, परंतु यह निश्चित नहीं है। अर्थव्यवस्था में न तो बचत और न ही निवेश अनुचित रूप से मंद हैं। सकल स्थिर पूंजी निर्माण और सकल घरेलू बचत स्तर तो 1990 के दशक में बने रहे स्तरों से कहीं अधिक उच्च हैं। 2000 के दशक में भारत में लगभग 10 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि हुई। इसके साथ ही साथ घरेलू बचत एवं निवेश दरों में अभूतपूर्व 9 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई। बाद में निवेश और बचत में आई गिरावट (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) ने इन दरों को सामान्य स्तरों की ओर ही मोड़ दिया है। विशेषकर-
  - सकल स्थिर पूंजी निर्माण और जीडीपी का अनुपात 2003 में 26.5 प्रतिशत से बढ़कर 2007 में 35.6 प्रतिशत के शीर्ष पर था और यह 2017 में गिरकर 26.4 प्रतिशत पर वापस आ गया।
  - घरेलू बचत और जीडीपी के अनुपात में भी इसी प्रकार का बदलाव दिखाई दिया है, जो 2003 में 29.2 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 29 प्रतिशत पर दोबारा गिरने के पहले 2007 में 38.3 प्रतिशत के शीर्ष पर था।
  - निवेश के लिये संचयी गिरावट 2007 और 2016 में बचत की तुलना में कम हुई है परंतु निवेश अधिक निचले स्तर तक गिर गया है।
- निवेश और बचत दरों में ऐसे तेज़ परिवर्तन भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं आए थे- 1991 में भुगतान शेष की समस्या के समय और न तो 1990 के आखिर में एशियाई वित्तीय संकट के दौरान। यद्यपि यह सच है कि समस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये विगत 15 वर्ष एक विशेष अवधि रही है, किंतु इस अवधि के दौरान किसी अन्य देश में इतनी बड़ी निवेश की धूम नहीं मची है और न ही गिरावट आई है। चित्र में दर्शाया गया है कि तुलनीय देशों में संकट के पहले बचत और निवेश में औसत वृद्धि कमतर रही जबकि बाद में केवल घरेलू बचत में तीव्र गिरावट देखी गई है। यद्यपि औसत मान हमेशा विभिन्न प्रकार के अनुभवों को छिपा जाते हैं, उसी अवधि में एक मात्र देश ब्राज़ील है, जिसने भारत की तरह पैटर्न दर्शाया है।

निवेश और बचत (जीडीपी के प्रतिशत में)

भारत



प्रतिदर्श अर्थव्यवस्थाओं के औसत



प्रतिदर्श में 55 देश हैं, कुछ कम आय (8) परंतु अधिकांश मध्यम आय (40) और कुछ उच्च आय (7) वाले।

http://t.me/Md_Ebooks

अभ्यास प्रश्न

1. निवेश और बचत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. 2000 के दशक में भारत में निवेश और बचत दरों में उच्च स्तरों पर पहुँचने के बाद से क्रमिक रूप से गिरावट हो रही है।
   2. निवेश में गिरावट की स्थिति में सुधार की गति धीमी है एवं निवेश में गिरावट का संवृद्धि पर प्रभाव पड़ता है।
   3. भारत में निवेश एवं बचत में गिरावट की प्रवृत्ति द्वितुलन पत्र की समस्या से जुड़ी हुई है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 2
   (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3
   (d) 1, 2 और 3

2. भारत में बचत और निवेश के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. 1991 में भुगतान शेष की समस्या एवं 1990 के एशियाई वित्तीय संकट के दौरान निवेश एवं बचत दरों में बहुत ही तीव्र परिवर्तन हुए थे।
   2. हाल ही में भारत में बचत और निवेश में हुई गिरावट के लिये मुख्यत: निजी निवेश, पारिवारिक बचत और सरकारी बचत आदि क्षेत्र ज़िम्मेदार हैं।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

3. 1980 के बाद से निम्नलिखित किस देश में बचत और निवेश में मंदी की घटनाएँ नहीं देखी गईं?
   (a) चीन
   (b) सिंगापुर
   (c) बांग्लादेश
   (d) मॉरीशस

4. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. 1997 के बाद एशियाई देशों को सर्वाधिक 10 बार मंदी का सामना करना पड़ा, इसलिये इसे 'पूर्वी एशियाई संकट' माना गया।
   2. पूर्वी एशियाई संकट के दौरान भारत में भी व्यापक स्तर पर मंदी की समस्या देखने को मिली।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

5. हाल ही में निवेश में गिरावट के बाद के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के दो रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. निवेश में हुई यह गिरावट तुलन पत्र से संबंधित थी।
   2. निवेश में 9 वर्षों की अवधि में चरम बिंदु से निम्नतम बिंदु तक 8.5 प्रतिशतांक की गिरावट हुई है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

6. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. सकल स्थिर पूंजी निर्माण और जीडीपी का अनुपात 2003 में 26.5 प्रतिशत से बढ़कर 2007 में 35.6 प्रतिशत के शीर्ष पर था और यह 2017 में गिर कर 26.4 प्रतिशत पर वापस आ गया।
   2. घरेलू बचत और जीडीपी का अनुपात 2003 में 29.2 प्रतिशत से बढ़कर 2010 में 29 प्रतिशत पर दोबारा गिरने के पहले 2007 में 38.3 प्रतिशत हो गया।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

7. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. यदि दो या अधिक लगातार वर्ष मंदी हो तो इसे 'मंदी का प्रकरण' माना जाता है।
   2. 1980 के दौरान लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में मंदी छाई रही, इन महाद्वीपों में इस अवधि को लुप्त दशक के नाम से जाना जाता है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरमाला

1. (d) 2. (b) 3. (c) 4. (a) 5. (c)
6. (c) 7. (c)

http://t.me/Md_Ebooks

4 राजकोषीय संघवाद और जवाबदेही में समन्वय : क्या इसमें निम्न संतुलन अवरोध है? (Reconciling Fiscal Federalism and Accountability : It there a Low Equilibrium Trap?)

"जिस गाँव के लोग स्वयं के लिये अपनी रोज़ी-रोटी, अपना स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा, अर्जित करने के लिये साथ आते हैं, उन्हें ऐसा करने का आनंद लेने के लिये, स्वराज के मार्ग में ज्योति जलानी होगी"

-रवींद्रनाथ टैगोर

राजकोषीय जवाबदेही उत्पन्न होने के साथ संस्थाएँ भी दीर्घ-कालीन तौर पर विकसित होती हैं। इसके लिये शायद अंतरित संसाधनों पर निर्भरता को कम करते रहने और कुल करों में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी बढ़ाने की ज़रूरत होती है। भारत में सरकार के दूसरे और तीसरे स्तर इन मानकों के सापेक्ष अपेक्षाकृत कम निष्पादन कर रहे हैं। इन स्तरों पर कर और अंतरित किये जाने वाले कार्य की सीमा इसकी एक संभावित व्याख्या हो सकती है। हालाँकि एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि ये स्तर अपनी शक्तियों की तुलना में काफी कम प्रत्यक्ष कर संग्रहण कर पाते हैं।

परिचय (Introduction)

- कर निर्धारण (कराधान) राज्य का राजस्व बढ़ाने का साधन मात्र नहीं है। यह आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिये भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो सकता है। बेसलो और पेर्सन (2013) की टिप्पणी के अनुसार नागरिकों और राज्य के मध्य एक सामाजिक संविदा होती है। 'राजस्व की भूमिका' अनिवार्य सेवाएँ प्रदान करके और पुनर्संवितरण (Redistribution) के माध्यम-से कम धनी व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करके सभी के लिये समृद्धि हेतु स्थितियाँ पैदा करना है। इस संविदा में नागरिकों की भूमिका राज्य के उस संविदा का सम्मान करने में विफल होने पर उसकी जवाबदेही को सँभालना होता है।
- किंतु यदि कोई नागरिक उन सेवाओं के लिये, जिन्हें राज्य मुहैया कराने के लिये प्रतिबद्ध है, सीधे तरीके से भुगतान नहीं करता, तो जवाबदेही के निर्वहन में उसका दायित्व धूमिल होता है। वह मुफ्त सवार (बिना भुगतान किये सेवा का लाभ उठाने वाला) बन जाता है और राज्य के घटिया गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने पर कोई शिकायत नहीं कर सकता है। यदि वह इससे (सेवा का बिल्कुल प्रयोग न करते हुए) बाहर जाता है, तो राज्य को जवाबदेह बनाए रखने की उसकी रुचि नहीं रहती है। वह राज्य को जवाबदेह बनाए रखने की तभी कोशिश करेगा जब वह सेवा के लिये भुगतान करके उसका लाभ उठाए। इसलिये यह अभिव्यक्ति होती है कि: कराधान के बिना कोई प्रतिनिधित्व नहीं। दूसरे शब्दों में, कराधान ऐसा आर्थिक सरेस (Glue) होता है जिससे नागरिक के राज्य से आवश्यक द्विमार्गी संबंध जुड़ते हैं।
- 'सहायता' और 'प्राकृतिक संसाधन' के अभिशाप यह चित्रित करते हैं कि जब देश सरकारी राजस्वों के गैर-कर स्रोतों पर निर्भर होते हैं, तो क्या होता है: आर्थिक एवं संस्थागत विकास उचित रूप से नहीं हो पाता।
- किंतु क्या यह सबसे व्यापक रूप से कराधान या विशेष रूप से प्रत्यक्ष कराधान (Direct Taxation) पर ही निर्भर करता है? ऐसा प्रतीत होता है कि नागरिकों का अंशभाग (Citizen's Stake) करों के भुगतान की अधिक परेशानी के समानुपाती होगा। जैसा कि स्वयं नाम से पता चलता है, प्रत्यक्ष करों का अनुभव करदाता द्वारा अधिक किया जाता है। प्रत्यक्ष करों का अनुभव स्वामित्वहरण (Expropriation) जैसा होता है क्योंकि इनसे नागरिकों की स्वयं प्रयोज्य आय और वे अर्जन कम हो जाते हैं जिन्हें वे अपने पास रखना चाहते हैं। अप्रत्यक्ष करों से, नागरिकों पर बोझ बढ़ जाता है किंतु बोझ का यह भाव उस बात पर छोड़ दिया जाता है कि नागरिक स्वयं विकल्प का चयन कर रहे हैं।

राजकोषीय संघवाद, कराधान और जवाबदेही से संबंधित मुद्दों के निरूपण में निम्नलिखित दो अंतर्राष्ट्रीय तथ्य मदद करते हैं-

प्रत्यक्ष कराधान और विकास : सरकार (केंद्र और राज्य) *(Direct Taxation and Development : General Government)*

- पहली बात यह है कि आर्थिक एवं राजनीतिक विकास कुल करों में प्रत्यक्ष करों के बढ़ते हुए हिस्से का अनुषंगी (Associated) रहा है।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) से प्राप्त डाटा का प्रयोग करके उन्नत और उभरते बाज़ारों वाले देशों के एक समूह के सह-संबंध से पता चलता है कि विकसित देश उभरते बाज़ारों की अपेक्षा प्रत्यक्ष करों से ही अपने राजस्व का उच्च अनुपात संग्रह करते हैं। दीर्घ काल में इस अनुपात में वृद्धि भी हुई है। पहले विकास प्रक्रिया में, आयात कर (अप्रत्यक्ष कर) और संपत्ति कर (आयकर) राजस्व के प्रमुख स्रोत थे, बाद में जैसे ही कल्याणकारी राज्यों का विस्तार होने लगा, यूरोप और यूएस में सरकार के संग्रहों को आयकरों में परिवर्तित कर दिया गया, ताकि उनके कर्मचारी सामाजिक बीमा में

http://t.me/Md_Ebooks

5 क्या विकास में विलंबित अभिसृति एक बाधा बन जाती है? क्या भारत इससे बच पाएगा? (Is there a "Late Converger Stall" in Economic Development? Can India Escape it?)

प्रियवर, यहाँ तो हमें अपने मुकाम पर ही बने रहने के लिये उतना तेज़ चलना होगा जितना हम चल सकते हैं और यदि तुम्हें इससे भी आगे कहीं जाना हो तो तुम्हें उससे दोगुनी रफ्तार से चलना होगा।

-लुईस कैरल एलिस इन वंडरलैंड

वर्तमान में विकासशील देशों के संबंध में सबसे पहली बात यह है कि ये देश एक अभूतपूर्व समृद्धि के दौर से गुज़र रहे हैं। यह बात भारत के संबंध में भी सत्य है जो विश्व की सर्वाधिक तेज़ी से परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। 'आर्थिक विकास की दौड़ में शामिल होना' इस समृद्धि को समुपस्थित करने में एक प्रमुख प्रेरक है जिसमें निर्धन देशों ने संपन्न देशों की तुलना में अधिक तेज़ी से प्रगति की है तथा जीवन-स्तरों में व्याप्त अंतराल को कम किया है। विकास की दौड़ में निरंतर शामिल होते रहने की प्रक्रिया गत 20-30 वर्षों के दौरान विस्तृत और त्वरित हुई है। तथापि, 'मध्यम आय पाश' (Middle Income Trap) की बाधाओं का भय काफी अधिक बताया जा रहा है, इसे देखते हुए क्या भारत जैसे निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों में यह प्रक्रिया मंद हो सकती है? वैश्विक वित्तीय संकट के दौर के बाद चार संभावित प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आर्थिक विकास की दौड़ में देरी से शामिल होने से विकास की गति बाधित होने की आशंका उत्पन्न हुई है जो इस दौर में शुरू में ही शामिल हो जाने वाले जापान तथा कोरिया जैसे देशों के संदर्भ में नहीं दिखी थी। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में शामिल हैं: वैश्वीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया जिसके कारण निर्यात अवसरों में कमी आती है, निम्न उत्पादकता से उच्च उत्पादकता क्षेत्रों में संसाधनों को अंतरित करने में कठिनाइयाँ (संरचनात्मक परिवर्तन), प्रौद्योगिकी गहन कार्यस्थलों की मांग के अनुरूप मानव पूंजी को उन्नत करने की चुनौती तथा कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन से प्रेरित दबावों का सामना करना। भारत ने अभी तक इन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी है किंतु उस दिशा में निरंतर प्रगति के लिये इन चुनौतियों का निर्णायक समाधान किया जाना आवश्यक होगा।

परिचय (Introduction)

- विश्व में व्याप्त संपूर्ण नैराश्य भाव के बावजूद मानवता के लिये तथा विशेषकर गरीब देशों में रहनेवाले लोगों के लिये यह दौर सर्वाधिक उपयुक्त आर्थिक प्रगति का दौर है। वर्तमान में विश्वभर में व्याप्त बुराइयाँ- युद्ध, हिंसा, अभाव तथा निर्धनता अभूतपूर्व निम्न स्तर पर हैं। इस समय विश्व स्तर पर व्याप्त अच्छाइयाँ-जीवन स्तर, आवश्यक सेवाओं तक पहुँच, तथा अधिक व्यापक रूप में भौतिक सुविधाओं तक पहुँच की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिससे ये इतने ऊँचे स्तर पर पहुँच गए हैं जो मानव जाति के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यह स्थिति विशेष रूप से भारत के संबंध में सत्य है जहाँ वर्ष 1980 के बाद सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है।
- आर्थिक अभिसृति (Economic Convergence) अर्थात् आर्थिक विकास की दौड़ में शामिल होना, निर्धन देशों द्वारा संपन्न देशों के समकक्ष आने तथा जीवन स्तर में व्याप्त अंतराल को कम करने की एक प्रक्रिया है, विकास के लिये इसने प्रेरक तत्त्व की तरह भूमिका निभाई है। 1980 के दशक के मध्य से निर्धन वर्ग के देशों के संपन्न वर्ग के देशों के समकक्ष आने (अभिसरण) की प्रक्रिया में तेज़ी आई है तथा ऐसे निर्धन देशों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है जिनमें अर्थव्यवस्था की विकास दर उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों की विकास दर की तुलना में अधिक तेज़ हुई है। इसके अतिरिक्त निर्धन देशों के अभिसरण (Catch-up) की दर में भी तेज़ी आई है। दूसरे शब्दों में "ये देश आर्थिक विकास की दौड़ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं।"
- इसके साक्ष्य के रूप में हम ऐसे अनेक देशों की तुलना कर सकते हैं जिनमें 1960-1980 तथा 1980-2017 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका (अपेक्षाकृत अधिक विकासशील देशों का एक प्रतिनिधि देश) की तुलना में अधिक तेज़ी से संवृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, हम यह तुलना भी कर सकते हैं कि इन अभिसृति कर रहे देशों में इन अवधियों के दौरान कितनी तेज़ी से संवृद्धि हुई है।

उग्र अभिसृति: संयुक्त राज्य अमेरिका के समकक्ष आना

अवधि	1960 से 1980 की अवधि	1980 से 2017 की अवधि
(Broadening: % of countries growing faster than US)	43.7%	68.6%
(Acceleration: Average excess growth rate over the US)	1.4%	1.7%
Countries in Sample	112	153

- स्वयं भारत का विकासक्रम उन्नयन अनुकरणीय है। वर्ष 1960 में भारत एक निम्न आय समूह में शामिल देश था, जिसकी प्रति व्यक्ति आय

http://t.me/Md_Ebooks

अभ्यास प्रश्न

1. बुनियादी गुरुत्व प्रतिमान (Gravity Model) पद से क्या अभिप्राय है?
   (a) छोटे देशों का बड़े देशों की तुलना में अधिक व्यापार करने की प्रवृत्ति।
   (b) छोटे देशों का बड़े की तुलना में कम व्यापार करने की प्रवृत्ति।
   (c) छोटे और बड़े देशों का आयात-निर्यात बराबर होना।
   (d) इनमें से कोई नहीं।

2. सफल विकास के अनिवार्य अवसंरचनात्मक परिवर्तनों के संदर्भ में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   1. संसाधनों के निम्न उत्पादकता से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में लगाना।
   2. संसाधनों का बड़ा भाग उन क्षेत्रों को समर्पित करना जिनमें उत्पादकता की तीव्र संवृद्धि की संभाव्यता हो।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

3. परिवर्तनों की सफलता सुनिश्चित करने में निम्न में से किस क्षेत्र की अहम भूमिका होती है?
   (a) सेवा क्षेत्र
   (b) कृषि क्षेत्र
   (c) विनिर्माण क्षेत्र
   (d) इनमें से कोई नहीं

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. एलपीसी (Learning Poverty Count) सामान्यत: उन बच्चों की संख्या की गणना करता है, जो सीखने के आधारभूत बैंचमार्क को पूरा नहीं करते।
   2. एलपीजी (Learning Poverty Gap) के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी बैंचमार्क से अंतराल को मापा जाता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

5. मध्यम आय समूह वाले देशों के संदर्भ में मध्यम आय समूह जाल/पाश से क्या आशय है?
   1. ये देश अपने आय स्तर की वजह से जन्मी उम्मीदों से कम दर से वृद्धि कर रहे हैं।
   2. ये देश अपने आय स्तर की वजह से जन्मी उम्मीदों से अधिक दर पर वृद्धि कर रहे हैं।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

6. प्रत्येक अवधि में विभिन्न आय समूह के देशों की संवद्धि दरों की तुलना की जाती है। इन विभिन्न आय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. निम्न आय समूह के देश वे हैं, जिनकी प्रतिव्यक्ति वास्तविक जीडीपी क्रय शक्ति समानता में अमेरिका में प्रतिव्यक्ति आय की तुलना में 5 प्रतिशत से कम हो।
   2. निम्न मध्यम आय समूह के देश वे हैं, जिनकी प्रतिव्यक्ति आय अमेरिका की तुलना में 5-15 प्रतिशत हो।
   3. उच्च मध्यम आय समूह के देश वे हैं, जिनकी प्रतिव्यक्ति आय अमेरिका की तुलना में 15-35 प्रतिशत हो।
   4. उच्च आय समूह वाले देश वे हैं, जिनकी प्रतिव्यक्ति आय उस स्तर से ऊपर या अमेरिका के आय स्तर से भी ऊपर हो।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 और 4
   (b) केवल 2, 3 और 4
   (c) केवल 2 और 3
   (d) 1, 2, 3 और 4

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. सफल विकास में दो तरह के संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता होती है।
   2. संसाधनों को निम्न उत्पादकता से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में लगाना और संसाधनों के बड़े हिस्से को उत्पादकता की तीव्र संवृद्धि की संभाव्यता वाले क्षेत्रों में लगाना सफल विकास के संरचनात्मक परिवर्तन के दो प्रमुख घटक है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरमाला

1. (a)	2. (c)	3. (c)	4. (d)	5. (a)
6. (d)	7. (c)			

http://t.me/Md_Ebooks

6 जलवायु, जलवायु परिवर्तन और कृषि (Climate, Climate Change and Agriculture)

मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती

मनोज कुमार, 'उपकार'

का बरषा जब कृषि सुखाने

-तुलसीदास, रामचरितमानस

इस अध्याय में तापमान, वर्षा और फसल उत्पादन संबंधी ज़िला-स्तर के आँकड़ों का प्रयोग करके बढ़ते तापमान, कम होती औसत वर्षा और प्रचंड वर्षा की घटनाओं में बढ़ोतरी के दीर्घकालिक रुझानों का वर्णन किया गया है। तापमान और वर्षा का प्रभाव केवल उनके प्रचंड होने की स्थिति में ही महसूस होता है; अर्थात् तब जब तापमान बहुत अधिक हो जाए, वर्षा बहुत ही कम हो और 'शुष्क दिवसों' की संख्या सामान्य से अधिक हो। ये प्रभाव असिंचित क्षेत्रों (और इसलिये वर्षापोषित फसलों पर) में अधिक प्रतिकूल हैं जबकि सिंचित क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप कृषि से होने वाली वार्षिक आमदनी में औसतन 15 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की कमी और असिंचित क्षेत्रों में 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के प्रति असुरक्षा को कम करने के लिये अपेक्षित है कि ("प्रत्येक बूंद से अधिक फसल" प्राप्त करने के लिये) कुशल ड्रिप एवं छिड़काव प्रौद्योगिकियों के ज़रिये सिंचाई का ज़बर्दस्त विस्तार किया जाए तथा विद्युत और उर्वरक में अलक्षित आर्थिक सहायता को प्रत्यक्ष आय सहायता से प्रतिस्थापित किया जाए। मोटे तौर पर, अनाज-केंद्रित नीति की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है।

परिचय (Introduction)

- मनोज कुमार के उस लोकप्रिय गीत में रूमानीकृत भारतीय कृषि उपज की प्रचुरता- जो प्रधानमंत्री के किसानों की आमदनी को दोगुना करने का आधार भी है- को भारतीय कृषि के समसामयिक यथार्थ और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अपनी कमज़ोर स्थिति की कठोर संभावनाओं का सामना करना है।
- पिछले कुछ मौसमों ने कई समस्याएँ देखी हैं। उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद, अनेक फसलों में किसानों की आमदनी में गिरावट हुई है क्योंकि बाज़ार कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमतों (MSP) से नीचे चली गई हैं। लेकिन मध्यम से दीर्घावधिक संदर्भ में, माल्थस का भूत (जनसंख्या का सिद्धांत) भारतीय कृषि पर मँडरा रहा है। संसाधनों से जुड़ी बढ़ती अड़चनों की पृष्ठभूमि में उत्पादकता बढ़ानी होगी और कीमत एवं आमदनी में व्याप्त अस्थिरता को कम करना होगा। जल और भूमि की कमी, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट और निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण हुई तापमान वृद्धि एवं वर्षा का उतार-चढ़ाव, कृषि को अवश्य प्रभावित करने वाले हैं। इसलिये, भारतीय कृषि पर जलवायु के प्रभाव का विश्लेषण करने का समय आ गया है।

कृषि का महत्त्व क्यों है : एक विडंबना (Why Agriculture Matters : An Irony)

- सबसे पहले तो, भारत में कृषि का महत्त्व बहुत गहरे कारणों से जुड़ा है। ऐसा केवल भारतीय मानस में किसान के किसी विशेष स्थान के कारण नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला आंदोलन वस्तुत: औपनिवेशिक शासन द्वारा शोषित किये गए नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। इतिहास, साहित्य और भारतीय लोक संस्कृति में किसान को मिथकीय दर्जा दे दिया गया है: भोला-भाला, निष्कपट, मेहनती जो प्रकृति के साथ घुला-मिला है, फिर भी वह गरीब, कमज़ोर और पीड़ित ही रहा है। पहले तो साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा और बाद में इस देश के भूमिपतियों और बिचौलियों द्वारा उसे सताया गया है।
- कृषि का महत्त्व आर्थिक कारणों से भी है क्योंकि यह अभी भी जीडीपी (16 प्रतिशत) और रोज़गार (49 प्रतिशत)का बड़ा हिस्सा प्रदान करती है। कृषि के खराब निष्पादन के कारण मुद्रास्फीति, किसानों पर दबाव और बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक असंतोष पैदा हो सकता है और ये सभी कारक अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकते हैं।
- नोबेल पुरस्कार विजेता सर आर्थर लुईस ने तर्क दिया था कि आर्थिक विकास का अर्थ सर्वदा और सर्वत्र लोगों को कृषि क्षेत्र से बाहर निकालने का है तथा समय के साथ-साथ कृषि को अर्थव्यवस्था का कम महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाने के संदर्भ में है (संपूर्ण अर्थ में नहीं लेकिन जीडीपी और रोज़गार के हिस्से के रूप में)। लेकिन यह प्रक्रिया उत्पादकता में तीव्र वृद्धि, लोगों के लिये अधिक खाद्य आपूर्ति, खेतों से बढ़ती आमदनी और संचित होती मानव पूंजी के संदर्भ में और उसके साथ-साथ चलनी चाहिये। कृषि मानव-आजीविका का प्रधान, स्थायी स्रोत क्यों नहीं हो सकता, इसका एक कारण उसका उत्पादकता स्तर है। इसका अर्थ यह है कि औद्योगीकरण और शहरीकरण को ही कृषि के मुकाबले अधिक उत्पादकता वाले विकल्प मुहैया कराने होंगे। किंतु यह कार्य कृषि में तीव्र उत्पादकता वृद्धि, जन-जन के लिये अधिक अनाज के उत्पादन, कृषि आय की निरंतर वृद्धि और मानवीय पूंजी के संकलन को बढ़ाने के संदर्भों में करना होगा।

http://t.me/Md_Ebooks

7 कन्या नहीं, पुत्र चाहिये : क्या विकास ही इस समस्या का समाधान है? (Gender and Son Meta-Preference : Is Development Itself an Antidote?)

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी
आँचल में है दूध और आँखों में पानी

-मैथिलीशरण गुप्त

वह चले लिये उत्तंग भाल,
सबकी आँखों में आँख डाल
निर्भीक, आत्मबल जन्मजात,
भयहीन पराक्रम का प्रपात
अदम्य साहस का छोर नहीं
अधुना नारी कमज़ोर नहीं।।

-सुब्रह्मण्य भारती, 'पुडुमाई पेन'

पिछले 10-15 वर्षों में, महिलाओं की क्षमता, दृष्टिकोण और परिणामों के संबंध में 17 में से 14 संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। इनमें से सात संकेतकों में सुधार कुछ ऐसा रहा है कि भारत की स्थिति विकास के स्तरों को मापने के बाद अनेक देशों के समान दिखाई देती है। उत्साहवर्द्धक बात यह है कि महिलाओं से जुड़े परिणाम समाभिरूपता का पैटर्न (Convergence Pattern) दर्शाते हैं, जो समान स्तर के देशों के मुकाबले भारत में काफी हद तक समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ बेहतर होते जाते हैं। दूसरे संकेतक, मुख्यत: रोज़गार और अपरिवर्तनीय गर्भनिरोध के प्रयोग और पुत्र की चाह के संबंध में, भारत को अभी कुछ दूरी तय करनी है क्योंकि विकास इस समस्या का समाधान सिद्ध नहीं हुआ है। भारत के भीतर ही, काफी विविधता दिखाई देती है, जहाँ पूर्वोत्तर राज्यों (देश के शेष भागों के लिये एक आदर्श) ने अन्य राज्यों के मुकाबले लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और यह इसलिये नहीं हुआ कि वे समृद्ध हैं। भीतरी राज्य इस संदर्भ में पिछड़ गए हैं लेकिन हैरानी इस बात की है कि कई दक्षिणी राज्य अपने विकास स्तरों की तुलना में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। महिला-पुरुष भेदभाव की चुनौती शायद सदियों से चली आ रही है, इसलिये सभी पक्ष समग्र रूप से इसके समाधान के लिये ज़िम्मेदार हैं। अधिक पुत्रों के लिये समाज की इस प्रबल चाह पर विचार करना चाहिये, जो विकास से अप्रभावित दिखाई देती है। महिलाओं और पुरुषों के प्रतिकूल लिंग अनुपात के कारण 'गुमशुदा' महिलाओं की समस्या की पहचान हो पाई है। लेकिन अधिक पुत्रों की चाह जनन क्षमता रोकने के नियमों से भी प्रतिबिंबित हो सकती है जो 'अवांछित' कन्याओं के वर्ग को जन्म देती है। ऐसी कन्याओं की संख्या 21 मिलियन के लगभग आँकी गई है। सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि निधि योजना और अनिवार्य मातृत्व अवकाश नियमावली सही दिशा में एक कदम है।

परिचय (Introduction)

- महिलाओं की भूमिका और स्थिति को उन्नत बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य को मान्यता प्रदान करने के साथ-साथ महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रमुख घटनाओं से निपटने के लिये सरकार ने जनवरी, 2015 में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान शुरू किया था। मोटे तौर पर 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का लक्ष्य जागरूकता लाने और सामाजिक मानदंडों को बदलने पर लक्षित जन अभियान के ज़रिये भारत में संतान लिंग अनुपात (Child Sex Ratio) की खराब स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित है। चूँकि विकसित देश महिलाओं के स्थानिक उत्पीड़न के प्रभाव से जूझ रहे हैं और चूँकि समाज में महिलाओं की भूमिका और हैसियत को बढ़ाने में आंतरिक और सहायक मूल्य के बारे में साक्ष्य मिल रहे हैं, अब यह प्रश्न करने का समय है: भारत का निष्पादन कैसा है और कितनी प्रगति हुई है? क्या भारत सुब्रह्मण्य भारती द्वारा वर्णित सशक्त महिला का देश है या फिर मैथिलीशरण गुप्त द्वारा व्यक्त अबला और दमित नारी का?
- लैंगिक समता के आंतरिक मूल्यों पर संदेह नहीं किया जा सकता लेकिन वर्तमान में इस बात का प्रमाण बढ़ रहा है कि यदि महिलाएँ और अधिक व्यक्तिगत क्षमता प्राप्त करती हैं, जैसे राजनीतिक शक्ति सँभालने, सामाजिक हैसियत प्राप्त करने और श्रम बल में बराबर की भागीदार बनती हैं तो आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण लाभ हो सकता है। विकासशील देशों में, कामकाजी महिलाएँ अपने बच्चों की शिक्षण व्यवस्था में भी अधिक निवेश करती हैं। अभी कुछ समय पहले दावोस में विश्व मुद्रा कोष के अध्यक्ष क्रिश्चियन लगार्डे ने कोष के शोध के हवाले से बताया है कि भारत में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के समान हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में 27 प्रतिशत का सुधार हो सकता है।
- दूसरा कारण लिंग और अन्य सामाजिक समस्याओं से संबंधित आकलनों को प्रभावित करने वाली संभावित व्यापक पद्धति समस्या को ठीक करना है। समस्या 'विकास काल' (Development Time) और 'आनुक्रमिक काल' (Chronological Time) को मिलाकर एक करने की है। लिंग सूचकांक जैसे वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) का वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का लिंग असमानता सूचकांक देशों के कालक्रम में स्थान निर्धारित करता है।
- लेकिन ऐसे साधारण समस्तरीय स्त्री-पुरुष तुलनाओं में एक गंभीर खामी है क्योंकि विकास के साथ महिलाओं की भूमिका उदित होती है।
- 'विकास काल' का सहारा 'आनुक्रमिक काल' को खारिज करने के लिये नहीं है और न ही यह 'कम उम्मीदों की उदार कट्टरता' (Soft

http://t.me/Md_Ebooks

निष्कर्ष *(Conclusion)*

- अनेक आयामों, विशिष्ट रूप से रोज़गार और प्रतिवर्ती गर्भ निरोधक के प्रयोग पर, भारत को अन्य देशों के समान होने के लिये कुछ सुधार करना पड़ेगा क्योंकि विकास स्वयं किसी उपाय के रूप में सिद्ध नहीं हुआ है।
- उत्साहवर्द्धक ढंग से, लिंग निष्कर्ष समाभिरूपता पैटर्न (Convergence Pattern) दर्शाते हैं। इनमें समान स्थिति वाले देशों की तुलना में भारत में संपदा के साथ-साथ इतना सुधार हो रहा है कि पीछे रहने वाले क्षेत्र में भी, समय के साथ समान स्थिति में आने की आशा की जा सकती है।
- इन अवलोकनों को ध्यान में रखकर, देश और सभी हितधारकों को शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में महिलाओं के लिये उपलब्ध उत्तरोत्तर अवसरों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'सुकन्या समृद्धि योजना' शुरू की हैं। सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नियोजित महिलाओं के लिये 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश को भी अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय में अब क्रेच की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है। इस संबंध में विकास की प्रबल ताकतों (Irresistible Force) और सांस्कृतिक मानकों वाले अटल उद्देश्यों के बीच इस असमान प्रतिस्पर्धा में, पूर्व वाले के लिये इसे प्रदान की जा सकने वाली पूर्ण नीतिगत सहायता आवश्यक होगी और तत्पश्चात् इसे किसी अन्य मदद की आवश्यकता होगी।
- जिस प्रकार भारत व्यापार करने की सरलता संसूचकों की रैंक में ऊपर बढ़ने के प्रति प्रतिबद्ध है, लिंग संबंधी वांछित परिणामों को हासिल करने हेतु ठीक वैसी ही प्रतिबद्धता रखनी होगी। यहाँ, लक्ष्य व्यापक होना चाहिये। बहुत से लिंग संबंधी परिणाम गहन सामाजिक प्राथमिकताओं को ज़ाहिर करते हैं, लड़कों को अत्यधिक वरीयता देने के फलस्वरूप, कई महिलाएँ 'गुमशुदा' हैं और लड़कियाँ 'अवांछित' हो गईं। अतः समग्र रूप से भारतीय समाज को चाहिये कि एक संकल्प लिया जाए। इसके लिये समाज को अभी बहुत कुछ करना है। ताकि जल्द ही यह कुत्सित विचार (पुत्र की अत्यधिक चाह) इतिहास बन जाए।

http://t.me/Ma_Ebooks

अभ्यास प्रश्न

1. महिलाओं की भूमिका के उन्नयन और दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के दृष्टिकोण से संबंधित कार्यक्रम कौन-कौन सा/से है/हैं?
   1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
   2. सुकन्या समृद्धि योजना
   3. मातृत्व अवकाश नियमावली

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 2
   (d) 1, 2 और 3
2. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने कोष के शोध के मुताबिक भारत में महिला पुरुष भागीदारी की समानता पर देश में कितने प्रतिशत के सुधार की बात स्वीकारी है?
   (a) 25 प्रतिशत
   (b) 28 प्रतिशत
   (c) 27 प्रतिशत
   (d) 30 प्रतिशत
3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के पूर्वोत्तर राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु इसका संबंध उनकी संपन्नता से नहीं बल्कि भीतरी राज्यों के खराब निष्पादन से है।
   2. भारत के दक्षिणी राज्य, जैसे- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश संपन्न होने के बावजूद लिंगानुपात की दृष्टि से खराब प्रदर्शन कर रहे हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. पुत्र की चाह लिंग चयनित गर्भपात को बढ़ावा देती है जिससे लिंगानुपात में विषमता पैदा होती है, परिणामस्वरूप 63 मिलियन महिलाओं के गुम हो जाने का अनुमान होता है।
   2. पुत्र की चाह से अनचाही लड़कियों की अनिच्छित श्रेणी बढ़ती है जो 21 मिलियन से अधिक है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरमाला

1. (d) 2. (c) 3. (d) 4. (c)

8 भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का रूपांतरण (Transforming Science and Technology in India)

हमें ज़रूरत है विजय की ऐसी भावना की, जो हमें विश्व में उस स्थान तक ले जाए जिसके हम अधिकारी हैं, ऐसी भावना जो यह स्वीकारे कि हम, जिन्हें विरासत में एक गौरवशाली सभ्यता मिली है, इस धरती पर वाकई उस स्थान के अधिकारी हैं। जब वह अदम्य भावना उभरेगी तो हमें अपना वैध प्रारब्ध (Rightful Destiny) हासिल करने से कोई नहीं रोक सकेगा।

-सी.वी.रमन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किये गए नवोन्मेष किसी भी राष्ट्र के दीर्घकालिक विकास और गतिशीलता का अभिन्न अंग होते हैं। विज्ञान के अनुसरण से जिज्ञासा और संवाद की ऐसी भावना पैदा होती है जो आधुनिक, खुले और लोकतांत्रिक समाजों के लिये बहुत महत्त्व रखती है। ऐतिहासिक दृष्टि से, भारत वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों में अपने अनेक योगदानों का उल्लेख कर सकता है। लेकिन भारत को अनुसंधान और विकास पर किया जाने वाला व्यय दोगुना करने की ज़रूरत है और अधिकांश वृद्धि निजी क्षेत्र और विश्वविद्यालयों से आनी चाहिये। नवोन्मेष की वह भावना फिर से पैदा करने के लिये, जो इसे वैश्विक स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय नेतृत्व प्रदान करे, ज्ञान के निवल उपभोक्ता से हटकर निवल उत्पादक बनाए, भारत को अपने युवा वर्ग को विज्ञान और गणित की शिक्षा देने पर ध्यान देना होगा, किये जा रहे अनुसंधान और विकास के तरीके में सुधार लाना होगा और डार्कमैटर, जिनोमिक्स, ऊर्जा भंडारण, कृषि और गणित तथा साइबर भौतिकी तंत्र जैसे क्षेत्रों में मिशन प्रेरित दृष्टिकोण अपनाना होगा। 'कारोबार करने में आसानी' (ease of doing business) की स्थिति को बेहतर बनाने के भारत के भागीरथ प्रयासों के साथ-साथ 'विज्ञान कार्यों में आसानी' (ease of doing science) लाने के भी प्रयास किये जाने होंगे।

विज्ञान क्यों? (Why Science?)

- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष (Innovation) किसी भी समाज के लिये सहायक और अंतर्निहित महत्त्व रखते हैं। वे आर्थिक उत्पादन और सामाजिक बेहतरी के मुख्य संचालक होते हैं। लेकिन वे कुछ और गहरे कारणों, जैसे- अदम्य जिज्ञासा वाली वैज्ञानिक भावना, तथ्यों और साक्ष्यों को दी गई प्राथमिकता, यथास्थिति को चुनौती देने की योग्यता, संवाद के मापदंडों का अनुपालन और संदेह व खुलेपन के महत्त्व से भी महत्त्वपूर्ण होते हैं। जिज्ञासा की खुली भावना जो विज्ञान का बुनियादी सिद्धांत है, वह इस समय विश्वभर में खतरनाक ढंग से उभर रही पुरातन पंथी, धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता की गहरी काली छायाओं के विरुद्ध सुरक्षा का काम कर सकती है।
- जैसे-जैसे भारत विश्व की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, वैसे-वैसे इसे ज्ञान के निवल उपभोक्ता (Net Consumer) से हटकर निवल उत्पादक (Net Producer) बनने की ज़रूरत है। विज्ञान में इसके अनेक ऐतिहासिक योगदान रहे हैं, जैसे- गणित के इतिहास में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान शून्य का पहला प्रयोग है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, संगमग्राम के माधव द्वारा किये गए योगदान से लेकर पिछली सदी में सी.वी. रमन, एस.एन. बोस, श्रीनिवास रामानुजन जैसे विज्ञानों द्वारा किये गए शानदार योगदान भी महत्त्वपूर्ण है।
- स्वतंत्र भारत ने भी अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं जिनमें परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से लेकर संकर बीज कार्यक्रम (Hybrid Seed Program) (हरित क्रांति की बुनियाद) और अंतरिक्ष कार्यक्रम जिसमें मंगलयान मिशन तक शामिल रहा है। इस मिशन ने किफायती और उच्च प्रौद्योगिकीय अनुसंधान करने में भारत की विशेषज्ञता को रेखांकित किया है। अभी हाल ही में, लेजर इंटरफैरोमीटर ग्रैवीटेशनल-वेव ऑब्जरवेटरी (लीगो) प्रयोग में भारत की महत्त्वपूर्ण भागीदारी (जिसमें तीन मुख्य भारतीय अनुसंधान संस्थाएँ शामिल थीं) ने गुरुत्व तरंगों के अस्तित्व के बारे में आइंस्टीन की भविष्यवाणी को सफलतापूर्वक सिद्ध किया। यही नहीं, भारत की वैक्सीनों तथा जेनेरिक दवाओं ने विश्वभर में लाखों लोगों की जानें भी बचाई हैं।
- लेकिन कोई भी देश विगत उपलब्धियों के सहारे ही बैठा नहीं रह सकता। एक ओर तो, वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान के विस्तार एवं रफ्तार की प्रचंडता तथा दूसरी ओर, भारत के युवावर्ग में इंजीनियरिंग, मेडिसिन, प्रबंधन के करिअर और सरकारी नौकरियों के आम तौर पर बढ़ते महत्त्व को देखते हुए, भारत को ऐसे प्रयोजन और उत्साह को फिर से जगाना होगा जो युवाओं को वैज्ञानिक उद्यमों की ओर अधिक आकर्षित कर सके। ऐसा करने से भारत की विकास से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिये ज्ञान संबंधी बुनियाद तो डाली ही जा सकेगी, साथ ही एक सभ्य व खुला समाज भी बन सकेगा। विज्ञान में निवेश करना भारत की सुरक्षा के लिये भी बेहद ज़रूरी है। इसकी आबादी के लिये मानव सुरक्षा; जलवायु परिवर्तन से उभरने वाली अनेकानेक अनिश्चितताओं का समाधान करने के लिये ज़रूरी समुत्थानशीलता और साइबर युद्ध से लेकर ड्रोन जैसे स्वायत्त सैन्य तंत्रों के कारण नए उभरते खतरों से आने वाली राष्ट्रीय सैन्य सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ भी अनदेखे नहीं किये जा सकते।

http://t.me/Md_Ebooks

9 व्यवसाय करने को आसान बनाने का अगला मोर्चा : समय से न्याय (Ease of Doing Business' Next Frontier : Timely Justice)

"कौन सहेगा समय-वक्त की मार
सितमगर के सितम
अब तो है बस न्याय की दरकार"

-हैमलेट

व्यवसाय तथा वाणिज्य (Business and Commerce) को आसान बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के परिणाम सामने आने लगे हैं। व्यवसाय करना आसान बनाने के लिये किये जा रहे प्रयासों का अगला मोर्चा अपीलीय तथा न्याय क्षेत्रों में लंबित, विलंबित तथा अनिर्णीत मामलों का निपटान करने से संबंधित है। इन स्थितियों के कारण विवाद समाधान (Dispute Resolution) तथा संविदाओं (Contracts) के क्रियान्वयन (Contract Enforcement) में बाधा उत्पन्न होती है, निवेश में कमी आती है, परियोजनाओं का क्रियान्वयन बाधित होता है, कर उगाही में अवरोध उत्पन्न होता है तथा अदालतों में मामलों पर खर्च बढ़ता है। कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका, ऊर्ध्वाधर सहकारी संघवाद (Vertical Cooperative Federlism) के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक प्रकार से शक्तियों का क्षैतिज सहकारी पृथक्करण (Horizontal Cooperative Separation) है। इनके बीच संयोजित/समन्वित क्रियाकलापों को करने से 'अदालतों में मामलों के निबटान में विलंब' की समस्या का समाधान होगा तथा आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा मिलेगा।

परिचय (Introduction)

- हिंदी फिल्म 'दामिनी' में न्यायालय के समक्ष अभिनेता सनी देयोल का प्रसिद्ध विलाप 'तारीख-पर-तारीख, तारीख-पर-तारीख' तथा विलियम शेक्सपीयर की नाट्य कृति हैमलेट के पात्र के उपर्युक्त कथन में पर्याप्त समानता है। ये दोनों अभिव्यक्ति के दो भिन्न-भिन्न रूप हैं। एक में अभिनेता चीख-चीख कर अत्यधिक भावुकतापूर्ण रूप में अपनी वेदना को अभिव्यक्त करता है तो दूसरे में नाटक का पात्र अत्यधिक सोच-विचार करके अपने मन की बात करता है, बावजूद इसके इन दोनों ही अभिव्यक्तियों द्वारा न्याय प्राप्त करने में विलंब और इस कारण न्याय से वंचित होने के कारण उत्पन्न हताशा को बलपूर्वक अभिव्यक्ति प्रदान करने में एक-सी भावना को प्रदर्शित किया गया है।
- भारत विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 में पहली बार 30 स्थान ऊपर उछलकर चोटी के 100 देशों की श्रेणी में शामिल हुआ है। इसकी यह रैंकिंग सरकार द्वारा व्यापक संसूचकों (Indicators) के संदर्भ में किये जा रहे सुधारात्मक उपायों को सूचित करती है। भारत कराधान तथा शोधन अक्षमता से संबंधित संसूचकों में क्रमशः 53 और 33 स्थान ऊपर आया है जो कराधान के क्षेत्र में किये गए प्रशासनिक सुधारों तथा शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) 2016 को पारित किये जाने के कारण हुआ है। इसने अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने तथा रोज़गार शुरू करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किये हैं तथा सरकार द्वारा बिजली उपलब्ध कराने के क्षेत्र में किये गए सुधारों के कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2017 में 70 स्थान ऊपर उठकर इसने बिजली प्राप्त करने के मामले में एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। इस वर्ष की रिपोर्ट में माल तथा सेवाकर (जीएसटी) जैसे अन्य उपायों को शामिल नहीं किया जिससे अगामी वर्षों में भारत की रैंकिंग में और अधिक सुधार होने की आशा है।
- बावजूद इस प्रेरक प्रगति के, भारत संविदाओं को अमली जामा पहनाने से संबंधित संसूचकों के मामले में लगातार पिछड़ रहा है किंतु जारी की गई हालिया रिपोर्ट में इसका स्थान 172 से थोड़ा-सा सुधरकर 164 पर पहुँचा है। इस रैंकिंग में यह पाकिस्तान, कांगो तथा सूडान जैसे देशों से भी पीछे है।
- आर्थिक वृद्धि तथा विकास में कारगर, दक्ष तथा शीघ्रतापूर्वक संविदा को प्रवर्तित करने के महत्त्व की अनदेखी नहीं की जा सकती। एक पारदर्शी तथा कुछ हद तक कानूनी एवं कार्यकारी व्यवस्था, जो दक्ष न्यायिक प्रणाली द्वारा समर्थित हो तथा नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की उपयुक्त रूप में सुरक्षा करती हो, संविदाओं की पवित्रता को बनाए रखती हो तथा संविदा में शामिल पक्षकारों के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को लागू करती हो, व्यवसाय तथा वाणिज्य की पूर्वापेक्षा है।
- सरकार ने संविदा में सुधार के लिये अनेक कदम उठाए हैं। उदाहरण के तौर पर अप्रयुक्त 1000 से भी अधिक कानूनों को समाप्त कर दिया, ट्रिब्यूनलों को युक्तिसंगत बनाया, मध्यस्थम तथा संराधन अधिनियम, 2015 (Arbitration and Conciliation Act, 2015) का संशोधन किया, वाणिज्यिक प्रभाग तथा वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 (Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015) पारित किया, अंतः सरकारी कानूनों (Intragovernment Litigation) की संख्या कम की, न्यायालय का बोझ कम करने के लिये लोक अदालत कार्यक्रम का विस्तार किया। सरकार ने कानूनी सांतत्य (Legal Consistancy) को सुनिश्चित करने के लिये और नियमों व विनियमों में अप्रत्याशित बदलाव की वजह से आने वाली अव्यवस्था में कमी लाने के लिये एक भावी कानूनी व्यवस्था की शुरुआती की है। न्यायपालिका में

http://t.me/Md_Ebooks

अभ्यास प्रश्न

1. भारत में व्यवसाय करने को आसान बनाने के सदंर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. भारत में व्यवसाय करना आसान बनाने के लिये अपीलीय तथा न्याय क्षेत्रों में लंबित, विलंबित तथा अनिर्णीत मामलों का निपटान करना आवश्यक है।
   2. न्यायलयों में लंबित, विलंबित तथा अनिर्णीत मामलों की वजह से संविदाओं एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है एवं निवेश में कमी आती है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

2. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है?
   (a) विश्व व्यापार संगठन
   (b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
   (c) विश्व बैंक
   (d) विश्व आर्थिक मंच

3. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. राज्यों तथा केंद्र द्वारा न्याय प्रशासन पर जीडीपी का कुल व्यय लगभग 0.08-0.09% होता है।
   2. भारत में राज्यों तथा केंद्र द्वारा न्याय प्रशासन पर किया जाने वाला खर्च जापान, नॉर्वे, आईसलैंड देशों की तुलना में बहुत कम है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

4. न्यायालयों की कुशलता को बढ़ाने एवं न्याय व्यवस्था प्रणाली को मित्तव्ययी बनाने के लिये निम्नलिखित में से किन-किन उपायों पर विचार किया जा सकता है?
   1. निचले न्यायालयों में न्याय व्यवस्था की क्षमता में विस्तार करना।
   2. उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के मौजूदा भार को कम करना।।
   3. न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु व्ययों में वृद्धि करना।
   4. न्यायालय मामला प्रबंधन तथा न्यायालय स्वचालन प्रणाली में सुधार करना।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1, 2 और 4
   (d) 1, 2, 3 और 4

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. न्याय व्यवस्था पर व्यय करने से लंबितता पर प्रभाव नहीं पड़ता, वहीं आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण और तकनीकी पर किये गए व्यय से औसतन सुनवाई अवधि में कमी आती है।
   2. किसी मामले की संपूर्ण अवधि का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा औपचारिक कार्यवाहियों जैसे- समन और नोटिस की तामील में व्यतीत हो जाता है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को सावधानीपूर्वक सीमित रिट से संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
   2. संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष छुट्टी याचिकाओं से उच्चतम न्यायालय का आर्थिक मुकद्मों संबंधी बोझ अधिक बढ़ गया है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

7. वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निम्नलिखित में से किस क्रम के अनुसार सुनवाई करते हैं?
   1. अनुपूरक मामले (नए मामले)
   2. नियमित मामले (अंतिम रूप से निपटान हेतु मामले)
   3. अग्रिम मामले (दर्ज मामले)

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) 2, 3 और 1
   (b) 1, 3 और 2
   (c) 1, 2 और 3
   (d) 3, 1 और 2

उत्तरमाला

1. (c) 2. (c) 3. (a) 4. (d) 5. (c)
6. (c) 7. (b)

http://t.me/Md_Ebooks

10 2017–18 में भारत के आर्थिक प्रदर्शन का सिंहावलोकन (An Overview of India's Economic Performance in 2017-18)

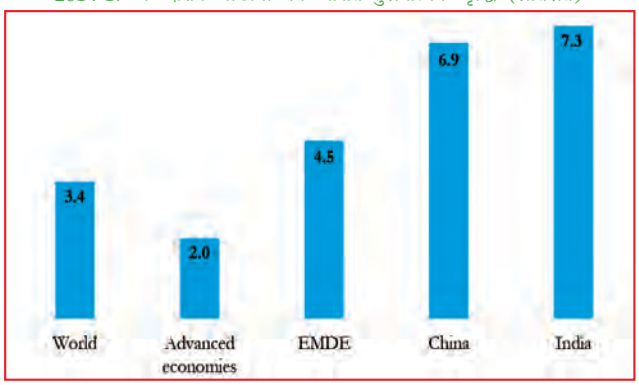
वर्ष 2016-17 में लगातार तीसरे वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक जीडीपी वृद्धि दर्ज करने के पश्चात् भारत की अर्थव्यवस्था कुछ धीमी वृद्धि की ओर अग्रसर हुई, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2017-18 में 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह हालिया घटनाक्रमों के आधार पर वर्तमान में पूर्वानुमानित 2017-18 में 6.5 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत के दायरे से थोड़ा-सा कम है। 2017-18 के लिये इस कमतर वृद्धि के साथ भी, 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लिये जीडीपी वृद्धि का औसत 7.3 प्रतिशत रहा है, जो विश्व के प्रमुख देशों में सबसे अधिक है। यह तथ्य कि यह वृद्धि कम मुद्रास्फीति, बेहतर चालू खाता शेष और जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय कमी के चलते हासिल की गई, इसे और अधिक सराहनीय बनाता है। माल और सेवा कर (जीएसटी) शुरू करने के अलावा, इस वर्ष बैंकों की अनर्जक आस्तियों से संबंधित समस्याओं के समाधान, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को और अधिक उदार बनाने आदि के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए, इस प्रकार सुधारों की गति और तेज़ की गई। दो वर्षों के लिये ऋणात्मक स्थिति में रहने के बाद, 2016-17 में निर्यात वृद्धि में दोबारा उछाल आया और 2017-18 में इसकी स्थिति और अधिक मज़बूत हो गई। जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर में बढ़ोतरी हुई और यह लगभग 414 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आस-पास रही।

2018 में वैश्विक वृद्धि में साधारण सुधार होने की संभावना है, अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी में अधिक स्थिरता की आशा, निवेश स्तर में संभावित सुधार और चालू अवसंरचनात्मक सुधार उच्चतर वृद्धि में सहायता करेंगे। कुल मिलाकर, देश के आर्थिक प्रदर्शन में 2018-19 में सुधार आना चाहिये।

2017–18 में जीडीपी में वृद्धि (GDP Growth in 2017-18)

- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का औसत 2014-15 और 2016-17 के बीच 7.5 प्रतिशत से अधिक रहने से, इस मानदंड पर भारत को विश्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देशों में गिना जा सकता है। पिछले 3 वर्षों के वैश्विक विकास औसत से यह वृद्धि 4 प्रतिशतांक से अधिक है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों द्वारा हासिल की गई औसत वृद्धि से लगभग 3 प्रतिशतांक अधिक है। यद्यपि 2017-18 में वृद्धि कम होकर 6.5 प्रतिशत रह सकती है, जो 4 वर्ष के औसत को 7.3 प्रतिशत पर ला देगी। यह वृद्धि पिछले 3 वर्षों की वैश्विक औसत वृद्धि से लगभग 4 प्रतिशतांक अधिक है और उभरते बाज़ारों एवं विकासशील देशों द्वारा हासिल औसत वृद्धि से लगभग 3 प्रतिशतांक अधिक है।

2014-17 के दौरान जीडीपी की औसत तुलनात्मक वृद्धि (प्रतिशत)



स्रोत: *आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनामिक आउट लुक डाटा बेस पर आधारित (अक्तूबर 2017)*

मुख्य संकेतक

सारणी-प्रमुख संकेतक	ईकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
जीडीपी और संबंधित संकेतक					
जीडीपी (2011-12 कीमतों पर)	₹ करोड़	10536984	11381002	12189854पीई	12985363एई
वृद्धि दर	%	7.5	8.0	7.1	6.5
आधार कीमतों पर जीवीए (2011-12 कीमतों पर)	₹ करोड़	9719023	10490514	11185440पीई	11871321एई
वृद्धि दर	%	7.2	7.9	6.6	6.1
बचत दर	जीडीपी का %	33.1	32.3	एनए	एनए

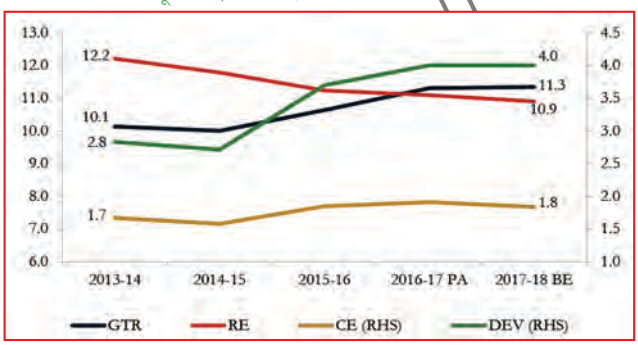
http://t.me/Md_EBooks

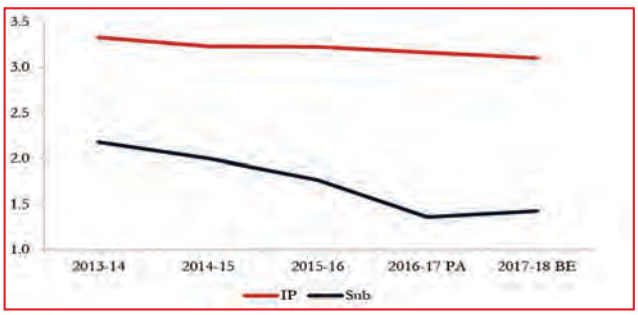
11 राजकोषीय घटनाक्रम की समीक्षा (Review of Fiscal Developments)

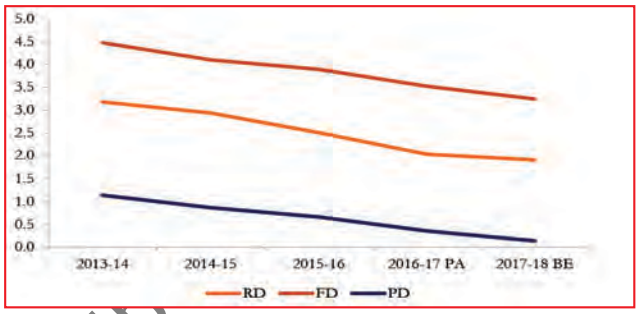
सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पिछले तीन वर्षों में भारत की स्थूल आर्थिक स्थिरता का एक स्तंभ रहा है। इस सख्त व्यवस्था के आधार पर, सरकार ने राज्यों की भागीदारी में, दीर्घ प्रतीक्षित माल एवं सेवा कर (जीएसटी) युग की शुरुआत की। जीएसटी को व्यापक तैयारियों, परिकलनों और बहुआयामी परामर्शों के बाद लागू किया गया था, फिर भी, बदलाव के मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब यह है कि आगामी अनिश्चितता और संभावित लागतों का सावधानीपूर्वक प्रबंध किये जाने की आवश्यकता है। सरकार परिवर्तन और चुनौतियों का पथ प्रदर्शन कर रही है, जिनमें यह संभावना भी शामिल है कि विगत माह के जीएसटी संग्रहों का अत्यधिक हिस्सा अगले वर्ष में जा सकता है। इस बीच, प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य के अनुरूप रहने की आशा है तथा व्यय संबंधी योजनाएँ व्यापक रूप से नियंत्रण में हैं।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में कर सुधारों को प्रवर्तित करने के लिये सरकार द्वारा प्रदत्त इस सुदृढ़ व्यवस्था को नीचे दिये गए रेखाचित्रों से समझा जा सकता है। राजस्व वृद्धि, व्यय गुणवत्ता, अंतरण और घाटे से संबंधित मुख्य राजकोषीय संकेतकों में पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय संकेतक







स्रोत: *सीजीए, लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार*

जीटीआर=सकल कर राजस्व; आरई=राजस्व व्यय; सीई=पूंजी व्यय; डीईवी=राज्यों के लिये कर हस्तांतरण; आईपी=ब्याज भुगतान; सब=सब्सिडी; आरडी=राजस्व घाटा; एफडी=राजकोषीय घाटा; पीडी=मूलघाटा; पीए=अनंतिम आँकड़े; बीई=बजट प्राक्कलन

नोट: यहाँ पर जिन रुझानों की चर्चा की गई है उनका संबंध मुख्यत: चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों से है।

केंद्र सरकार की प्राप्तियाँ और व्यय (Receipts and Expenditure of the Central Government)

प्राप्तियाँ *(Receipts)*

- केंद्र सरकार के नवंबर 2017 तक के वित्तीय आँकड़े नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीजीए) से प्राप्त किये गए हैं। नवंबर 2017 तक राजस्व के संबंध में तीन विशिष्ट स्वरूप देखने को मिले हैं जिनकी झलक केंद्र की गैर-ऋण प्राप्तियों से संबंधित रुझानों में दिखाई देती है।

अप्रैल-नवंबर के दौरान केंद्र सरकार की प्राप्तियाँ

	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
	(₹ लाख करोड़ में)			बजट प्राक्कलन का प्रतिशत (पूरे वर्ष के लिये)		
सकल कर राजस्व	7.68	9.33	10.87	53.0	57.2	56.9
निवल कर राजस्व (केंद्र के लिये)	4.65	6.21	6.99	50.5	58.9	57.0
गैर-कर राजस्व	1.73	1.75	1.05	78.1	54.2	36.5
राजस्व प्राप्तियाँ	6.38	7.96	8.05	55.9	57.8	53.1
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.21	0.33	0.62	25.8	48.5	73.3
गैर-ऋण प्राप्तियाँ	6.59	8.29	8.67	53.9	57.4	54.2

स्रोत: *लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार*

//t.me/Md_EJ

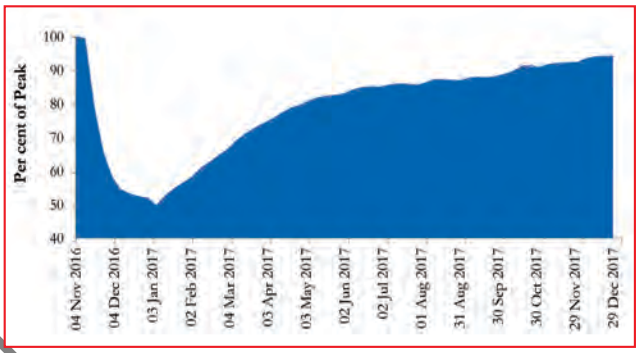
12 मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता (Monetary Management and Financial Intermediation)

वर्ष 2017-18 के दौरान (जनवरी तक), मौद्रिक नीति स्थिर बनी रही जिसमें अगस्त में केवल एक पॉलिसी दर में कटौती की गई। जैसे-जैसे नोटबंदी का वर्षानुवर्ष प्रभाव घटता गया, संचलन में मुद्रा और एम 0 दोनों की वृद्धि दरें तेज़ी से सकारात्मक हो गईं। 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति की आय में सितंबर 2017 से स्थिरता आई है। वर्ष 2017-18 में शोधन अक्षमता और दिवालियापन की नई प्रक्रिया के लिये अर्थतंत्र बना। बैंकिंग क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों की समस्या को सुलझाने के लिये आईबीसी तंत्र का सक्रिय प्रयोग किया जा रहा है।

वर्ष 2017-18 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम (Monetary Developments During 2017-18)

- वर्ष 2017-18 के दौरान मौद्रिक नीति 5 अगस्त, 2016 से लागू संशोधित सांविधिक फ्रेमवर्क के तहत संचालित की गई। इस लेख को लिखते समय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पाँच बैठकें आयोजित की जा चुकी थीं (जनवरी, 2018 तक)। अगस्त 2017 में जारी वर्ष 2017-18 के लिये तीसरे द्वैमासिक मौद्रिक नीति विवरण में एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी करके उसे 6.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। अक्तूबर तथा दिसंबर में हुई अपनी हालिया बैठकों में एमपीसी ने इन दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया। तदनुसार, तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.25 प्रतिशत बनी रही।
- पुन:मौद्रीकरण प्रक्रिया के अनुरूप वित्त वर्ष 2017-18 में 10 नवंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान आरक्षित निधि (एम0) में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर में आनुक्रमिक वृद्धि हुई किंतु यह ऋणात्मक बनी रही तथा पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम स्तर पर बनी रही जिससे विमुद्रीकरण का प्रभाव सुस्त तथा अपेक्षाकृत उत्तरोत्तर क्षीण होता हुआ दिखाई दिया। 17 नवंबर, 2017 से एक अनुकूल आधार प्रभाव प्रारंभ हुआ तथा परिचलन में मुद्रा (सीआईसी) तथा आरक्षित निधि (एम0) में तेज़ी से बदलाव हुआ तथा ये धनात्मक स्तर पर पहुँच गई तथा पिछले वर्ष की संगत वृद्धि दर की तुलना में उच्च स्तर पर आ गई। 29 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार एम0 में 55.9 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 28.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ऐसा मुख्य रूप से परिचलन में स्थित मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि (80.4 प्रतिशत, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 40.2 प्रतिशत की कमी आई थी) के कारण हुआ। परिचलन में मुद्रा विमुद्रीकरण के पूर्व की स्थिति तुलना में 94.19 प्रतिशत दर्ज की गई।

चरम स्थिति के प्रतिशत के रूप में परिचलन में स्थित मुद्रा (सीआईसी)



स्रोत: *आरबीआई*

- स्रोत पक्ष से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एम0 में वृद्धि एलएएफ रिवर्स रेपो (निवल) में कमी द्वारा तथा आरबीआई की निवल विदेशी परिसंपत्तियों में वृद्धि द्वारा प्रेरित हुई है। तथापि, सरकार को आरबीआई द्वारा दिये गए निवल ऋण में खुले बाज़ार में निवल बिक्री तथा साथ ही सरकारी जमा में वृद्धि के कारण कमी आई है।
- एम 3 में विमुद्रीकरण के बाद वर्षानुवर्ष वृद्धि की दर मंद हुई है किंतु एम0 में हुई कमी की तुलना में यह धनात्मक स्तर पर है। इसका कारण यह है कि जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में आई कमी सकल जमा राशि में वृद्धि द्वारा अंशत: संतुलित हो गई। वर्ष 2017-18 के दौरान विस्तृत मुद्रा (एम 3) में वर्षानुवर्ष वृद्धि में तेज़ी आई, जिसकी मुख्य रूप से सितंबर अंत, 2017 से शुरुआत हुई तथा पहली बार 24 नवंबर 2017 को इसमें पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई जो अनुकूल आधार प्रभाव को दर्शाती है। इसी तारीख को सीआईसी और एम 3 का अनुपात 12.6 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 9.8 प्रतिशत था। स्रोत के अनुसार यद्यपि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गए ऋण में धीमी गति से हुई वृद्धि 2017-18 से अब तक की अवधि के दौरान एम 3 की वृद्धि में सहायक हुई है।

नकदी की स्थिति और इसका प्रबंधन (Liquidity Conditions and its Management)

- नवंबर 2016 के आरंभ में विमुद्रीकरण के बाद रिज़र्व बैंक ने पारंपरिक

http://t.me/M

13

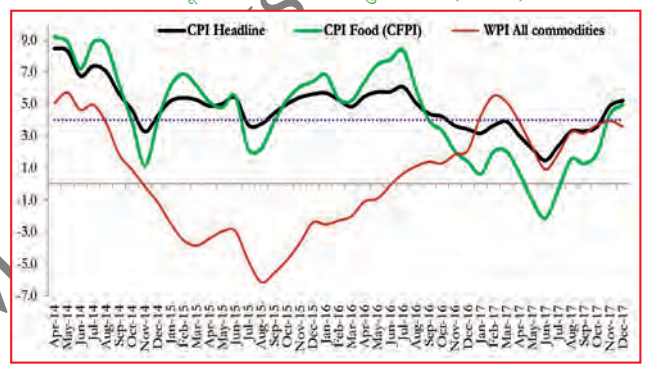
कीमतें और मुद्रास्फीति
(Prices and Inflation)

देश में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान मुद्रास्फीति (Inflation) का कम होना जारी रहा। अप्रैल-दिसंबर 2017-18 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति का औसत 3.3 प्रतिशत था। यह पिछले छह वित्तीय वर्ष में सबसे कम थी। खाद्य मुद्रास्फीति विशेषकर दालों और सब्ज़ियों में बहुत अधिक कमी आने से सामान्य मुद्रास्फीति कम हुई। अप्रैल-दिसंबर 2017-18 के दौरान औसत खाद्य मुद्रास्फीति गिरकर 1.2 प्रतिशत पर आ गई। इस अवधि के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति भी गिरी। वर्ष के दौरान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बहुत से राज्यों में मुद्रास्फीति गिरावट देखी गई।

परिचय (Introduction)

- अर्थव्यवस्था में पिछले चार वर्षों में उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति से धीरे-धीरे स्थिर कीमतों की ओर पारगमन हुआ है। लगातार चौथे वर्ष के लिये उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा मापी गई हेड लाइन मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की शुरुआत 3.0 प्रतिशत वार्षिक मुद्रास्फीति दर से हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली दो तिमाहियों में कीमतों में सामान्य सी वृद्धि हुई थी, इसके परिणामस्वरूप पहली तिमाही में 2.2 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 3.0 प्रतिशत पर मुद्रास्फीति का स्तर नीचे रहा। हेड लाइन मुद्रास्फीति दर 2017 के जून महीने में 1.5 प्रतिशत पर अपनी शृंखला में कमतर आ गई। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक (Consumer Food Price Index) द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 1.2 प्रतिशत पर नीचे गिर गई।
- थोक कीमत सूचकांक की नई शृंखला (2011-12) पर आधारित औसत मुद्रास्फीति 2016-17 में 1.7 प्रतिशत रही जबकि 2015-16 में (–) 3.7 प्रतिशत और 2014-15 में 1.2 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के लिये थोक कीमत सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 2.9 प्रतिशत रही।

थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)



मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृतियाँ (Current Trends In Inflation)

- औसत सीपीआई- संयुक्त (CPI–Combined) मुद्रास्फीति 2014-15 में 5.9 प्रतिशत और 2015-16 में 4.9 प्रतिशत से कम होकर 2016-17 में 4.5 प्रतिशत हो गई थी। वित्त वर्ष 2017-18 में औसत मुद्रास्फीति (अप्रैल-दिसंबर) में 3.3 प्रतिशत थी, जो 4 प्रतिशत के आरंभिक स्तर से काफी कम थी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मुद्रास्फीति

विभिन्न सूचकांकों के अनुसार सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अप्रै.-दिसं.)*
डब्ल्यूपीआई	6.9	5.2	1.2	-3.7	1.7	2.9 (P)
सीपीआई (संयुक्त)	10.2	9.5	5.9	4.9	4.5	3.3 (P)
सीपीआई (आईडब्ल्यू)	10.4	9.7	6.3	5.6	4.1	2.3#
सीपीआई (एएल)	10.0	11.6	6.6	4.4	4.2	2.0#
सीपीआई (आरएल)	10.2	11.5	6.9	4.6	4.2	2.1#

स्रोत: *थोक कीमत सूचकांक के लिये औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, उपभोक्ता कीमत सूचकांक (संयुक्त) के लिये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और सीपीआई (आईडब्ल्यू), सीपीआई (एएल) तथा सीपीआई (आरएल) के लिये श्रम ब्यूरो।*

टिप्पणी: *पुरानी शृंखला 2010=100 पर आधारित 2012-13 और 2014-15 के लिये उपभोक्ता कीमत सूचकांक (संयुक्त) मुद्रास्फीति।*

पी-अनंतिम, आईडब्ल्यू-औद्योगिक कामगार, एएल-कृषि श्रमिक और आरएल-ग्रामीण श्रमिक।

#2017-18 (अप्रैल-नवंबर) की अवधि के लिये

**अप्रैल-दिसंबर 2017 के दौरान मुद्रास्फीति, अप्रैल-दिसंबर 2016 से नौ महिनों के लिये मासिक सूचकांक के औसत की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2017 से नौ महिनों के लिये मासिक सूचकांक के औसत में प्रतिशत परिवर्तन है।*

http://t.me/M

वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत एफएओ की खाद्य कीमतों में वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) के 3.2 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 5.8 प्रतिशत की उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

मुद्रास्फीति रोकने के लिये प्रयास (Efforts To Control Inflation)

केंद्रीय सरकार नियमित आधार पर कीमतों की स्थिति पर नज़र रखती है क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना प्राथमिकता का क्षेत्र है। मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्यान्न मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं-

- आवश्यक होने पर, जमाखोरी और कालाबाज़ारी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने, आवश्यक वस्तु अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के लिये कालाबाज़ारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु अनुरूप अधिनियम, 1980 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये राज्य सरकारों को अनेक सुझाव जारी किये जा रहे हैं।
- कीमत और उपलब्धता स्तर के संबंध में शीर्षस्थ स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। ये बैठकें सचिवों की समिति, अंतर-मंत्रालयी समिति, कीमत स्थिरीकरण निधि, प्रबंधक समिति तथा अन्य विभागीय स्तर की समीक्षा बैठकों के स्तर पर की जाती है।
- खाद्य पदार्थों के लिये अधिकतम समर्थन कीमतें (एमएसपी) घोषित की गई हैं ताकि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और ऐसा कर खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई जा सके जिससे कीमतें कम करने में मदद मिलेगी।
- दाल, प्याज आदि कृषि वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिये कीमत स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) नामक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- सरकार ने दालों के सुरक्षित भंडार (बफर स्टाक) को 1.5 लाख मी. टन से बढ़ाकर 20 लाख मी. टन करने को अनुमोदित कर दिया है ताकि खुदरा कीमतों को न बढ़ने देने के लिये कारगर बाज़ारी हस्तक्षेप किया जा सके। तदनुसार घरेलू खरीद तथा आयात के मध्यम से कीमत स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के अंतर्गत दालों का 20 लाख टन तक का गतिशील सुरक्षित भंडार तैयार किया गया है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने, मध्याह्न भोजन योजना आदि के लिये सुरक्षित भंडार से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दालें दी जा रही हैं।
- सरकार ने चीनी के निर्यात पर 20% उत्पाद शुल्क लगाया ताकि उपलब्धता को बढ़ाया जा सके और बढ़ती कीमत को कम किया जा सके।
- शून्य सीमा शुल्क पर 5 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई। इसके बाद 25% सीमा शुल्क पर अतिरिक्त 3 लाख टन के आयात की अनुमति प्रदान की गई।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्याज की भंडार सीमा (स्टॉक सीमा) तय करने की सलाह दी गई है। राज्यों से अनुरोध किया गया था कि अपनी प्याज की मांग के बारे में सूचित करें ताकि उपलब्धता बढ़ाने और मौजूदा ऊँची दर में कमी लाने के लिये आवश्यक मात्र में आयात की कार्रवाई शुरू की जा सके।

निष्कर्ष (Conclusion)

आवास (Housing) एवं ईंधन तथा प्रकाश (Fuel and Light) समूह को छोड़कर सभी बड़ी वस्तु समूहों में मुद्रास्फीति में व्यापक कमी आने से वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति में 3.3 प्रतिशत रह गई। नवंबर 2016 से अक्तूबर 2017 तक 12 माह तक मुख्य मुद्रास्फीति (हेडलाइन इनफ्लेशन) 4 प्रतिशत से कम रही है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति औसतन एक प्रतिशत के आस-पास रही है।

http://t.me/Ml_Ebooks

अभ्यास प्रश्न

1. आवास कीमत सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   1. एक भौगोलिक सीमा के भीतर रिहायशी संपत्ति की कीमतों में उतार-चढ़ाव को मापने के लिये आवास कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है।
   2. प्रथम आवासीय कीमत सूचकांक एनएचबी-रेसिडेक्स को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किया गया था।
   3. राष्ट्रीय आवास बैंक आवासीय कीमत सूचकांक की गणना करने के लिये वित्तीय वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग करता है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1
   (c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3
2. भारत में थोक कीमत सूचकांक (WPI) निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?
   (a) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
   (b) भारतीय रिज़र्व बैंक
   (c) औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग
   (d) श्रम ब्यूरो
3. मुद्रास्फीति को रोकने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-कौन सा/से प्रयास किये जा रहे है/हैं?
   1. खाद्य पदार्थों के लिये अधिकतम समर्थन कीमतें (एमएसपी) घोषित की गई हैं ताकि खाद्य वस्तुओं का उत्पादन एवं उपलब्धता बढ़ाई जा सके, जिससे उनकी कीमतें कम हो सकें।
   2. दाल, प्याज़ आदि कृषि वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिये कीमत स्थिरीकरण निधि नामक योजना शुरू की गई है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरमाला

1. (c) 2. (c) 3. (c)

14 धारणीय विकास, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन (Sustainable Development, Energy and Climate Change)

भारत ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, संपोषणीय कृषि, संपोषणीय पर्यावास, जल, वानिकी, हिमालयी पारिस्थितिकी प्रणाली, और ज्ञान तथा क्षमता निर्माण से संबंधित अनेक कार्यक्रम चलाता रहा है और उन्हें प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर रहा है। अत: भारत भी यह उम्मीद करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समान और साझे सिद्धांतों परंतु अपने-अपने दायित्वों का अनुपालन करने में उत्सुक होगा और वचनबद्धताओं को पूरा करेगा।

धारणीय/सतत् विकास के लक्ष्य (Sustainable Development Goals)

- सितंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे व्यापक रूप से शामिल हैं जिन्हें सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) के आधार पर तैयार किया गया था। ध्यातव्य है कि धारणीय विकास लक्ष्यों में सभी प्रकार और सभी रूपों में व्याप्त गरीबी जिसमें चरम गरीबी भी शामिल है, को समाप्त करने के लिये एक सार्वभौमिक करार किया गया है। कुल मिलाकर 17 धारणीय विकास लक्ष्य हैं जिनके 169 उद्देश्य हैं और उन्हें सन् 2030 तक प्राप्त करना है। भारत ने इन धारणीय विकास लक्ष्यों को तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सरकार के अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे धारणीय विकास लक्ष्य के एजेंडे को आगे बढ़ाने में प्रत्यक्ष योगदान मिलेगा। इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' (पीएमजेडीवाई) है जो विश्व का सर्वाधिक विशाल वित्तीय समावेशी कार्यक्रम है। जब हम आर्थिक ढाँचागत विकास और औद्योगिकीकरण को लक्ष्य बनाते हैं तो यह देश की गरीबी के लिये लड़ी जाने वाली लड़ाई मुख्यत: सामाजिक समावेशन और गरीबों के सशक्तीकरण पर केंद्रित हो जाती है। राष्ट्रीय विकास एजेंडे और धारणीय विकास लक्ष्यों से संबंधित भारत की वचनबद्धता को बल प्रदान करते हुए भारत की संसद में निर्धनता उन्मूलन, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने और जलवायु परिवर्तन संबंधी नीति तैयार करने और कार्रवाई संबंधी अनेक मंच तैयार किये गए हैं। भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) 2017 पर स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) में स्वैच्छिक रूप से भाग लिया था। भारत ने 19 जुलाई, 2017 को संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच में धारणीय विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन पर अपनी पहली स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की थी। समीक्षा रिपोर्ट देश में विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रयासों के अंतर्गत की गई प्रगति के विश्लेषण पर आधारित है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 7 धारणीय विकास लक्ष्यों पर केंद्रित है- गरीबी की समाप्ति (1); शून्य भुखमरी (2); अच्छा स्वास्थ्य (3); लैंगिक समानता (5); उद्योग, नवोन्मेष और बुनियादी सुविधाएँ (9); जलीय जीवन (14) और लक्ष्यों के लिये भागीदारी (17)।

राष्ट्रीय धारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) संकेतक और आधार रेखा *(National SDG Indicators and Baseline)*

- संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग द्वारा स्वीकृत वैश्विक धारणीय विकास लक्ष्यों के आलोक में केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य विभिन्न हितार्थियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय धारणीय विकास लक्ष्य संकेतक विकसित किये जा रहे हैं और ये इस समय अंतिम रूप प्रदान करने के अग्रिम चरण में हैं। कार्यान्वयन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक सतत् निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी और वर्ष 2016 को आधार वर्ष मानते हुए धारणीय विकास लक्ष्यों की प्रगति संबंधी विश्वसनीय सूचना और साक्ष्य तैयार किये जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग की भूमिका विस्तृत प्रचार-प्रसार के लिये धारणीय विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना को संग्रह करने, देने और सर्वोत्तम व्यवहारों को दस्तावेज़बद्ध करने की होगी। धारणीय विकास लक्ष्यों की प्रगति का आकलन नियमित आधार पर एक समेकित डैशबोर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

शहरी भारत और सतत् विकास (Urban India And Sustainable Development)

- धारणीय विकास के 11वें लक्ष्य में शहरों को समावेशी, सुरक्षित, रहने लायक और सातत्य प्रदान करना शामिल हैं। भारत बड़ी तेज़ी के साथ शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। चूँकि शहर आर्थिक कार्यकलापों के केंद्र होते हैं इसलिये कोई शहर धारणीय विकास के मार्ग पर प्रगति कर रहा है या नहीं, इस बात का निर्धारण शहरों द्वारा प्रदान की जा रही बुनियादी सेवाओं की संख्या पर निर्भर करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के धारणीय विकास के एजेंडे को कार्यरूप प्रदान करने वाले मानदंडों को परिभाषित करने वाले संकेतकों में से एक शहरी भारत द्वारा चुना गया विकास पथ होगा।

http://t.me/Md_Ebooks

प्रभावी कार्रवाई के लिये कई सुझाव (राष्ट्रीय हरित अधिकरण और उच्चतम न्यायालय के निर्णय; टेरी 2016; इंडीकस फाउंडेशन, 2017, और अन्य) दिये गए हैं जिनमें से कुछ पर कार्य प्रारंभ हो चुका है: **अल्पावधिक आपात योजना** (जब पीएम 2.5 24 घंटे के दौरान 300-400 $\mu g/m^3$ से अधिक हो जाता है): उपग्रह आधारित उपकरणों का प्रयोग करते हुए कृषि अपशिष्ट को जलाने पर भारी दंड लगाकर कठोर कार्रवाई करना, आग का पता लगाना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मोबाइल आधारित एप्लीकेशन्स लागू करना; राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना।

मध्यम और दीर्घावधि कार्य: एनसीआर में सभी वाहनों के लिये संकुलता कीमत निर्धारण का कार्यान्वयन निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाने के लिये तथा मेट्रो एवं मेट्रो से इतर क्षेत्रों तक संपर्क स्थापित करने के लिये सरकारी बसों की सेवा का तेज़ी से विस्तार एवं संवर्द्धन करना, पुराने वाहनों को चलन से बाहर करना, बीएस-VI मानक (पहले से अधिसूचित और 2020 से लागू होना प्रस्तावित) को अपनाने में गति लाना तथा आधुनिकीकृत बस स्टेंडों का विस्तार करना।

कृषि अपशिष्टों को उपयोज्य संकेंद्रित चारा या बायो-फ्यूल में रूपांतरित करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, प्राइवेट सेक्टर और समुदायों के साथ किये जाने वाले व्यावसायिक मॉडल का विकास एवं कार्यान्वयन करना तथा गैर-धान फसल उगाने को प्रोत्साहित करना। दूसरे शब्दों में, फसल अवशिष्टों, जैसे- फर्टिलाइजर लागतों को कम करना, बिजली बनाने आदि के लिये गोबर के उपयोग से जुड़े व्यावसायिक मामलों का अन्वेषण करना ताकि इनके आर्थिक मूल्य प्राप्त हो सके। इस तरह का एक उदाहरण चावल और गेहूँ के बारे में पराली प्रबंधन प्रणाली का है। हैप्पी सीडर मशीन नामक प्रौद्योगिकी इसका एक संभावित प्रौद्योगिकीय समाधान हो सकता है। यह एक ऐसी मशीन है जो धान की पराली को हटाए बिना अगली फसल के बीजों को फैला देगी और जब पराली प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से खेत में पराली को समान रूप से फैला दिया जाता है तब यह अच्छी तरह से कार्य करती है। केंद्र और राज्यों द्वारा इसमें अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हुए इस प्रौद्योगिकीय समाधान को इसके अर्थशास्त्र से जोड़े जाने तथा इसका कार्यान्वयन कृषि सहकारिता, स्थानीय निकायों, आदि के माध्यम से कराए जाने की आवश्यकता है।

प्रगति पथ (Way Forward)

- वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2018 में भारत को शीर्षस्थ छह सर्वाधिक सुभेद्य (Vulnerable) देशों में शामिल किया गया है। यह बताया गया है कि अत्यधिक गरीब आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जिनमें जलवायु परिवर्तन की संभावना होती है और उनके व्यवसाय भी अत्यधिक जलवायु संवेदी होते हैं, जैसे- मत्स्य पालन। इसके साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में प्रकटन के स्तर और व्यक्तियों, परिवारों तथा समुदायों की अंतर्निहित ग्रहण क्षमताओं के स्तर के अनुसार अत्यधिक भिन्नता होगी। धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत के प्रयासों से अनेक सक्रिय परिणाम सुनिश्चित हुए हैं। प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये असीम वित्तीय अपेक्षाएँ हैं। फिर भी जलवायु परिवर्तन को नीति निर्णयों में अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। यहाँ तक कि 15वें वित्त आयोग ने जलवायु परिवर्तन को विचार के लिये एक महत्त्वपूर्ण पहलू के रूप में उल्लेख किया है।
- आगामी वर्षों में वित्त व्यवस्था संबंधी ऐसी अनिश्चितताओं को कम करने के लिये, विकसित देशों के लिये यह आवश्यक है कि वे अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारियों पर आधारित प्रतिबद्धताओं और समता के सिद्धांत तथा सामान्य किंतु विशिष्ट ज़िम्मेदारियों का अनुपालन करें। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अपने हिस्से की उचित ज़िम्मेदारियों पर कार्रवाई करने से हमारे नभ मंडल के लिये निम्न कार्बन जलवायु प्रतिरोधी विकास का मार्ग मिलेगा।

http://Md-Ebooks

अभ्यास प्रश्न

1. धारणीय विकास के लक्ष्यों को बल देने वाले भारत की प्रथम स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट (वीएनआर) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट देश में विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रयासों के अंतर्गत की गई प्रगति के विश्लेषण पर आधारित है।
   2. 'स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट' 17 धारणीय विकास लक्ष्यों पर केंद्रित हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. विश्व आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2013 के अनुसार शहरों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये चार स्तंभों- सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण प्रबंधन और प्रभावी शहरी शासन के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।
   2. संयुक्त राष्ट्र विश्व धरोहर रिपोर्ट 2016 के मुताबिक भारत में वर्ष 2030 तक 7 मेगासिटी होंगे जिनकी आबादी दस मिलियन से अधिक होगी।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

15 वैदेशिक क्षेत्र (External Sector)

भारत का विदेशी (बाह्य) सेक्टर वर्ष 2017-18 में अब तक, काफी लोचदार और सशक्त बना रहा। वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही (एच-1) में भुगतान संतुलन के चालू लेखा घाटे का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.8 प्रतिशत होने का सुखद अनुभव जारी है। वाणिज्य वस्तु के निर्यातों में अप्रैल-दिसंबर 2017 में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उछाल आया, निवल सेवा प्राप्तियों में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि रही, और वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में निवल विदेशी निवेश बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गया तथा विदेशी कर्ज के सूचकों में सुधार रहा। इन प्रमुख सुधारों को कार्यान्वित करते समय प्रारंभिक चुनौतियों से उबरने में बजट में सहायक कार्रवाइयों, विदेशी व्यापार नीति की मध्यावधिक समीक्षा और जीएसटी से संबंधित सामयिक नीति परिवर्तनों से मदद मिली।

वैश्विक आर्थिक परिवेश (Global Economic Environment)

अंतर्राष्ट्रीय विकासक्रम *(International Developments)*

- वैश्विक अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है और उम्मीद है कि इसकी संवृद्धि दर वर्ष 2016 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में 3.6 प्रतिशत और वर्ष 2018 में बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो जाएगी जो आईएमएफ द्वारा दिये गए पूर्व अनुमानों के ऊर्ध्वगामी सुधार (Upward Revision) को दर्शाता है। विश्व के विकास में यह ऊर्ध्वगामी सुधार यूरो क्षेत्र, जापान, उभरते हुए एशिया और रूस में वर्ष 2017 की प्रथम छमाही में आशान्वित परिणामों से बेहतर योगदान के कारण रहा है, भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यू.के. में अधोगामी परिवर्तन (Downward Revision) रहे हैं। विश्व व्यापार का परिमाण (Volume) वर्ष 2016 में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में 4.2 प्रतिशत होने और वर्ष 2018 में 4.0 प्रतिशत होने की आशा है। पिछले वर्षों की गिरावट के प्रतिकूल उपयोगी वस्तुओं (तेल और गैर-ईंधन) की कीमतों के भी बढ़ने की आशा की जाती है। आईएमएफ (अक्तूबर 2017) के अनुसार, वैश्विक समुत्थान (Recovery) अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि मुद्रास्फीति अधिकतर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अभी भी लक्ष्य से नीचे है और उपयोगी वस्तुओं के निर्यातक, विशेष रूप से ईंधन निर्यातक तेल की कीमतों में गिरावट के कारण विफल रहे हैं। यद्यपि अल्पकालिक जोखिम व्यापक रूप से संतुलित हैं, किंतु मध्यावधिक जोखिम अभी भी अधोगामी दिशा में है।

भारत के भुगतान संतुलन संबंधी प्रगति (India's Balance of Payments Developments)

भुगतान संतुलन का सिंहावलोकन *(Overview of Balance of Payments)*

- भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति वर्ष 2013-14 से काफी अच्छी है और वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में चालू खाते के घाटे (सीएडी) में कुछ बढ़ोतरी होने के बावजूद तथा द्वितीय तिमाही में चालू खाते में अपेक्षाकृत कमी होने के साथ ही वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में

http://t.me/Md_Ebooks

वैश्विक उत्पादन और व्यापार (माल और सेवाएँ) अनुमानों का सिंहावलोकन

	Actual	Projections		Difference from July 2017 WEO Update	
	2016	2017	2018	2017	2018
विश्व उत्पादन	3.2	3.6	3.7	0.1	0.1
विश्व व्यापार परिमाण (माल और सेवाएँ)	2.4	4.2	4.0	0.2	0.1
आयात					
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ	2.7	4.0	3.8	0.0	0.2
ईएमडीईएस	2.0	4.4	4.9	0.1	0.2
निर्यात					
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ	2.2	3.8	3.6	-0.1	0.2
ईएमडीईएस	2.5	4.8	4.5	1.0	0.0

स्रोत: *आईएमएफ, विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन, अक्तूबर 2017*
नोट: *ईएमडीईएस-उदीप्यमान बाज़ार और विकासशील, अर्थव्यवस्थाएँ।*

16 कृषि एवं खाद्य प्रबंधन (Agriculture and Food Management)

कृषि केवल फसल का उत्पादन नहीं है जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, वरन् यह विश्व की भूमि और जल से रोटी और कपड़े का उत्पादन है। कृषि के बिना शहर, स्टॉक बाज़ार, बैंक, विश्वविद्यालय, चर्च या सेना का अस्तित्व संभव नहीं है। कृषि किसी भी सभ्यता और स्थिर अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। – ***एलन सेवरी***

भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, गरीबी कम करने और विकास को बनाए रखने में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। कृषि में उत्पादकता में सुधार लाने में सिंचाई, बीज, उर्वरक और मशीनीकरण जैसे महत्त्वपूर्ण साधनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि विकास के गतिशील घटक फसल क्षेत्र के हिस्से में गिरावट और कृषि उपक्षेत्रों के हिस्से में वृद्धि परिलिक्षित कर रहे हैं। चूँकि कृषि क्षेत्र उत्पादन, मौसम, कीमतों और नीति से जुड़े जोखिमों से ग्रस्त रहता है, इसलिये आय सृजित करने वाले कार्यकलापों में विविधता लाकर कृषि क्षेत्र में ढाँचागत परिवर्तनों से लाभ उठाकर इन जोखिमों को कम किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था में विकास की गति बनाए रखी जा सकती है।

- भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास की यह प्रक्रिया अन्य बातों के साथ-साथ, सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) में कृषि के गिरते हिस्से में परिणत होती है, जो भारत में भी देखी जा रही है। फिर भी, यह गिरता हिस्सा रोज़गार, आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिये इस क्षेत्र के महत्त्व को कम नहीं कर देता। कृषि में संरचनागत परिवर्तनों के चलते, उत्पादकता में सुधार लाने और सतत् विकास के अवसरों के लिये कृषि से संबंधित कार्यकलापों को व्यापक बनाने की बड़ी संभावना है।

कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों पर एक नज़र (Overview Of Agriculture And Allied Sectors)

- कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों की विकास दरों में उतार-चढ़ाव होता रहा है जो 2012-13 में 1.5 प्रतिशत, 2013-14 में 5.6 प्रतिशत, 2014-15 में (–) 0.2 प्रतिशत, 2015-16 में 0.7 प्रतिशत और 2016-17 में 4.9 प्रतिशत रही। भारत में 50 प्रतिशत कृषि वर्षा पर आश्रित है जिससे उत्पादन संबंधी जोखिम और बढ़ जाती है, इसी वजह से कृषि क्षेत्र में अनिश्चितताएँ बनी रहती हैं।

कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation In Agriculture And Allied Sector)

- जीवीए के संदर्भ में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई है जो 2011-12 के 18.2 प्रतिशत से 2015-16 में 16.4 प्रतिशत हो गया। कुल जीसीएफ के अनुपात के रूप में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों के सकल पूंजी निर्माण में गिरावट देखी गई जो 2014-15 के 8.3 प्रतिशत से कम होता हुआ 2015-16 में 7.8 प्रतिशत रह गया।

कृषि क्षेत्र-मुख्य संकेतक

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 अ.अ
2011-12 मूल्य पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में जीवीए वृद्धि (प्रतिशत में)	1.5	5.6	-0.2	0.7	4.9
चालू कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का कुल जीवीए में हिस्सा (प्रतिशत में)	18.2	18.6	18.0	17.5	17.4
वर्तमान मूल्य पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का कुल सकल पूंजी निर्माण में हिस्सा* (प्रतिशत में)	7.7	9.0	8.3	7.8	उ.न.
फसलों का हिस्सा*	6.5	7.7	6.9	6.5	उ.न.
पशुधन का हिस्सा*	0.8	0.9	0.8	0.8	उ.न.
वानिकी एवं लागिंग का हिस्सा*	0.1	0.1	0.1	0.1	उ.न.
मात्स्यिकी का हिस्सा*	0.4	0.5	0.5	0.5	उ.न.

स्रोत: *केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय*
* *परिकलन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2017 पर आधारित; उ.न. = उपलब्ध नहीं*

फसल उत्पादन 2016–17 (Production Of Crops 2016-17)

- कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किये गए

https://t.me/Md_EBooks

अभ्यास प्रश्न

1. भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र का महत्त्व परिलक्षित होता है-
   1. आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने में
   2. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में
   3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करने में
   4. उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने में

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 (d) 1, 2, 3 और 4

2. भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. भारत के कृषि क्षेत्र में कृषि कार्यों, फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन, बागवानी, फसल-पश्चकार्य, मत्स्य पालन और वानिकी सहित अन्य कृषि विकास कार्यों में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हो रही है।
   2. जनगणना-2011 के अनुसार, कुल महिला कामगारों में से 55 प्रतिशत कृषि श्रमिक और 24 प्रतिशत खेतिहर महिलाएँ थीं।
   3. भारत में कृषि में जोत क्षेत्रों के स्वामित्व में लैंगिक असमानता प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि प्रचालनरत जोत क्षेत्रों में मात्र 12.8 प्रतिशत का स्वामित्व महिलाओं के पास है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

3. कृषि क्षेत्र में महिलाओं के विकास एवं महत्त्व को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किये गए हैं?
   1. सभी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं बजट आवंटन में महिलाओं को कम-से-कम 30 प्रतिशत का आवंटन करना।
   2. महिलाओं तक विभिन्न लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम/योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने के लिये महिला केंद्रित कार्यकलाप आरंभ करना।
   3. महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना एवं सूक्ष्म ऋण प्रदान कर उनका क्षमता निर्माण करना।
   4. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देते हुए 2 अक्तूबर को महिला किसान दिवस घोषित किया है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

4. कृषि आगतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. भारत के कुल प्रचालन जोत क्षेत्र में प्रमाणित बीजों एवं संकर बीजों का भाग क्रमशः 9.4 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत है।
   2. गुणवता युक्त बीजों के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिये बीज बदलाव दर तथा ऊर्ध्वाधर बदलाव दर को प्रोत्साहन देने के लिये कृषि फसलों में बीज उत्पादन वाली बीज परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
   3. उर्वरक तथा संकर बीजों के उपयोग से तभी अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है जब सिंचाई सुविधाएँ पर्याप्त हों।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 3
   (c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

5. कृषि आगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. आगत सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार अनुमानित 138.11 मिलियन प्रचालनरत जोतदारों में लगभग 70 प्रतिशत कृषक अशिक्षित हैं।
   2. कुल सीमांत तथा छोटे किसानों में से लगभग 30 प्रतिशत अशिक्षित हैं।
   3. लघु एवं सीमांत जोत क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकियों का उपयोग, जोखित न्यूनीकरण उपायों को अपनाने एवं कृषकों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करना आवश्यक है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 2 (d) 1, 2 और 3

6. भारत में किसानों द्वारा फसलों का बीमा न करवाने का/के प्रमुख कारण है/हैं-
   1. किसानों का फसल बीमा के प्रति जागरूक न होना
   2. किसानों में इच्छा शक्ति का अभाव
   3. फसल बीमा सुविधाओं की अपर्याप्त कवरेज और पहुँच
   4. जटिल प्रक्रियाएँ
   5. अच्छी फसल बीमा योजनाओं का अभाव

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
   (c) 1, 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

7. निम्नलिखित में से 'जलवायु स्मार्ट कृषि' का/के उद्देश्य है/हैं-
   1. कृषि उत्पादकता और आय को सतत् रूप से बढ़ाना।
   2. जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुकूलता को अंगीकार करना।
   3. ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन को कम करना।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

8. खाद्य प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रबंधन, केंद्र और राज्यों के बीच आपस में सम्मेलित संगठनात्मक ढाँचे द्वारा किया जाता है।
   2. खाद्य प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत सरकार किसानों को उचित कीमत प्रदान करने, कम आय वाले उपभोक्ताओं को किफायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने, बफर स्टॉक का रखरखाव करके आकस्मिकता एवं कमी के लिये खाद्यान्न को स्टॉक करने और खाद्य कीमत अस्थिरता को कम करने का प्रयास करती है।
   3. सरकार द्वारा खाद्य आर्थिक सहायता पर किये जाने वाले व्यय में पिछले पाँच वर्षों से सतत् वृद्धि हो रही है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरमाला

1. (d) 2. (d) 3. (c) 4. (d) 5. (d)
6. (c) 7. (d) 8. (b)

http://t.me/Md_EBooks

17

उद्योग और अवसंरचना
(Industry and Infrastructure)

प्रतिष्ठित, विकासोन्मुखी उद्योगों को सहायता देने के साथ-साथ ऐसी कर नीतियाँ अपनाना जिनसे छोटे कारोबार का विकास हो और निवेश को बढ़ावा मिले, यही एक ऐसा ज़बर्दस्त फॉर्मूला है जो हमारे समस्त प्रशासन का आधार है।

-लैरी होगन

हमें यह सोचना बंद कर देना चाहिये कि अवसंरचना एक आर्थिक संचालक है, बल्कि इसे कार्यनीति के रूप में देखना शुरू कर देना चाहिये। आर्थिक संचालक ऐसे सेतुओं का निर्माण करते हैं जो आपको कहीं नहीं पहुँचाते। अवसंरचना में कार्यनीतिक निवेश से दीर्घकालिक विकास की बुनियाद का निर्माण होता है।

-रोजर मैकनमी

समावेशी रोज़गार प्रधान उद्योग को बढ़ावा देना और समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण आर्थिक संवृद्धि और विकास के महत्त्वपूर्ण कारक हैं। सरकार इस दिशा में अनेक क्षेत्र-विशिष्ट उपाय कर रही है। कारोबार करने में आसानी के लिये वस्तु और सेवा कर, शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता जैसे ढाँचागत सुधारों के अलावा सरकार ने इस्पात, वस्त्र, चमड़ा और विद्युत क्षेत्र में अनेक विशिष्ट सुधार किये हैं ताकि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के साथ जुड़ी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान किया जा सके। पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा किये गए विभिन्न सुधारों को अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों जैसे कि मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस द्वारा स्वीकारा गया है और विश्व बैंक रिपोर्ट 2018 के 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में भारत के स्थान में उछाल आया है। इस अध्याय में उद्योग और अवसंरचना में व्याप्त मौजूदा रुझानों के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण उपायों और उपलब्धियों की चर्चा की गई है। सड़क, रेलवे, मेट्रो रेल, पोत परिवहन, नागर विमानन, विद्युत, संभारिकी अवसंरचना (Logistics Infrastructure) में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है जिससे अल्पावधि में वृद्धि के गति पकड़ने की संभावना है। सड़क क्षेत्र में नीतिगत हस्तक्षेप से संबंधित भाग में रुकी हुई परियोजनाओं और अनर्जक आस्तियों जैसी समस्याओं, राष्ट्रीय राजमार्गों का और अधिक निर्माण करने के लिये और राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में रूपांतरित करने के लिये किये गए उपायों तथा ज़िला सड़कों का अधिकाधिक विकास करने से संबंधित व्यापक नीति की ज़रूरत पर चर्चा की गई है।

उद्योग (Industry)

वर्ष 2014 से सरकार द्वारा की गई कई उद्योग विशिष्ट सुधार पहलों ने देश में समग्र कारोबारी माहौल को महत्त्वपूर्ण रूप से सुधारा है। सुधार प्रक्रिया केंद्र और राज्य सरकारों को कवर करते हुए उपयोगिता और कवरेज की दृष्टि से व्यापक रही है। परिणामस्वरूप, भारत ने विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में अपने पिछले 130वें रैंक से 30 रैंक की उछाल लगाई है। क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडीज़ इनवेस्टर्स सर्विस ने भारत की रेटिंग बीएए 3 के न्यूनतम निवेश ग्रेड से बढ़ाकर बीएए 2 कर दी है।

- यह सरकार द्वारा किये गए अनेक उपायों के कारण संभव हुआ है जिसमें वस्तु और सेवा कर का कार्यान्वयन, दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code), बैंकों के पुनर्पूंजीकरण (Bank Recapitalization) की प्रणाली और घोषणा तथा मुद्रास्फीति के लक्ष्य निर्धारण की शुरुआत शामिल है। कारोबार को आसान बनाने में सुगमता लाने के अन्य उपायों में औद्योगिक लाइसेंस और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के लिये ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ और सरलीकरण, ई-बिज पोर्टल के साथ बीस सेवाओं को जोड़ना, जो

क्षेत्रीय सकल मूल्यवर्द्धन में वृद्धि (%)

	जीवीए* में हिस्सा	2015-16	2016-17	2017-18	
				ति.1	ति.2
खान और खदान	3.0	10.5	1.8	-0.7	5.5
विनिर्माण	18.1	10.8	7.9	1.2	7.0
बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ	2.2	5.0	7.2	7.0	7.6
निर्माण	8.0	5.0	1.7	2.0	2.6
उद्योग	**31.2**	**8.8**	**5.6**	**1.6**	**5.8**

स्रोत: *केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय*
नोट: **जीवीए में हिस्सा जोकि 2016-17 में है। (स्थिर मूल्यों पर)*

http://t.me/Prep_Ebooks

18

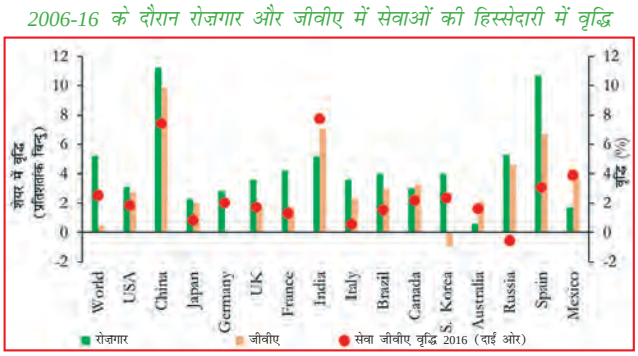
सेवा क्षेत्र
(Service Sector)

भारत के सकल मूल्य वर्द्धन (Gross Value Added) में 55.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख संचालक बना हुआ है। 2017-18 में सकल मूल्य वर्द्धन वृद्धि (Gross Value Added Growth) में लगभग 72.5 प्रतिशत का योगदान रहा। यद्यपि इस क्षेत्र की वृद्धि 2017-18 में 8.3 प्रतिशत होने का अनुमान है, 2017-18 के पूर्वार्द्ध में सेवा निर्यात (Services Export) और निवल सेवाओं (Net Services) में वृद्धि क्रमशः 16.2 प्रतिशत और 14.6 प्रतिशत के सुदृढ़ स्तर पर रही। सरकार ने विभिन्न सेवाओं में बहुत-सी पहलें की हैं जिनमें डिजिटलीकरण, ई-वीज़ा, संभार तंत्र (Logistics) को अवसंरचना का दर्जा देना, स्टार्ट-अप-इंडिया, आवास क्षेत्र के लिये योजनाएँ आदि शामिल हैं, जिनसे इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएँ (International Comparisons)

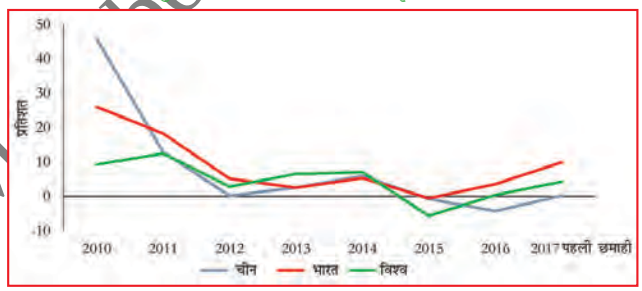
संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (UN National Accounts Statistics) के आँकड़ों के अनुसार, विश्व के 15 बड़े देशों में समग्र जीडीपी के अनुसार भारत का स्थान 2006 में 14वें से सुधरकर 2016 में 7वें पर आ गया। इन शीर्ष 15 देशों में, चीन ने (9.8 पीपी) 2006-16 के दौरान सकल मूल्य वर्द्धन में सेवाओं की हिस्सेदारी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, इसके बाद भारत (7.1 पीपी) और स्पेन (7.0 पीपी) का स्थान आता है। वर्ष 2016 में, सेवा जीवीए वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर) भारत में 7.8 प्रतिशत पर सबसे अधिक थी, इसके बाद चीन की 7.4 प्रतिशत पर थी। आईएलओ अनुमानों के अनुसार 2016 में शीर्ष 15 देशों में, भारत और चीन को छोड़कर अधिकांश में कुल रोज़गार के दो-तिहाई से भी अधिक का योगदान सेवा क्षेत्र का था, भारत का हिस्सा 30.6 प्रतिशत पर सबसे कम था। जबकि 2006 से 2016 की अवधि के दौरान चीन के सेवा रोज़गार के हिस्से में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी (10.2 पीपी) भारत में यह वृद्धि केवल 5.2 पीपी थी।

2006-16 के दौरान रोज़गार और जीवीए में सेवाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि



सेवा निर्यात वृद्धि, विश्व और भारत दोनों के लिये, 2009 से 6 वर्षों के अंतराल के बाद 2015 में गिरकर ऋणात्मक हो गई थी, 2016 में घनात्मक स्थिति में आ गई। विश्व व्यापार संगठन के अद्यतन आँकड़ों के अनुसार, 2017 की पहली छमाही के लिये विश्व के लिये सेवा निर्यात वृद्धि 4.3 प्रतिशत (पहली और दूसरी तिमाही का औसत) और भारत के लिये 9.9 प्रतिशत पर थी, फिर भी रूस द्वारा 18.4 प्रतिशत सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। चीन की वृद्धि 0.2 प्रतिशत थी।

वर्षानुवर्ष वाणिज्यिक सेवा निर्यात वृद्धि (प्रतिशत)



भारत का सेवा क्षेत्र (India's Service Sector)

सेवाओं का सकल मूल्य वर्द्धन *(Services of GVA)*

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय 2017-18 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान सेवा क्षेत्र में वृद्धि (जीवीए 2011-12 की आधार कीमतों पर) 8.3 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो वर्ष 2016-17 में हुई 7.7 प्रतिशत से अधिक है।

भारत के सेवा क्षेत्र का हिस्सा और विकास (आधार मूल्य पर जीवीए)

	शेयर (प्रतिशत)		वृद्धि (प्रतिशत)	
	2015-16	2015-16	2016-17@	2017-18#
सभी सेवाएँ	52.9	9.7	7.7	8.3
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तराँ	11.4	11.2	7.8*	8.7*
व्यापार और मरम्मत सेवाएँ	10.4	10.9	–	–
होटल और रेस्तराँ	1.0	14.4	–	–
परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	7.0	9.3	–	–
रेलवे	0.8	7.0	–	–

http://t.me/M...Books

19 सामाजिक अवसंरचना, रोज़गार और मानव विकास (Social Infrastructure, Employment and Human Development)

अर्थशास्त्रियों को बहुत पहले से ही ज्ञात है कि लोग राष्ट्रों की संपदा के ज़रूरी घटक हैं।

-टी.डब्ल्यू. शल्ट्ज

भारत में समावेशी और सतत् विकास लाने के लिये, सामाजिक अवसंरचना जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। सरकार मानव संसाधन पर व्यय भी बढ़ाती रही है और साथ ही योजनाओं का विलय करके व्यय की कार्यक्षमता को बढ़ाने के उपाय भी करती रही है। रोज़गार सृजन के अवसर पैदा करने तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर कार्यरत जनता को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिये विधायी सुधार तथा श्रम सुधार के अनेक उपाय लागू किये जा रहे हैं। शिक्षा, कौशल विकास, रोज़गार, आमदनी में स्त्रियों से जुड़े अनानुपातिक अंतरालों को पाटना और सामाजिक विषमता को कम करना मानव सामर्थ्य को संवर्द्धित करने की विकासपरक कार्यनीति के मूल लक्ष्य रहे हैं।

मानव संसाधन में निवेश राष्ट्र निर्माण करने वाली स्वस्थ और उत्पादक जनता के लिये पूर्व अपेक्षा है। विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण, भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्त्वपूर्ण सामाजिक अवसंरचना पर व्यय बढ़ाने की पर्याप्त वित्तीय गुंजाइश नहीं है। तथापि, सीमित संसाधनों को देखते हुए, सरकार ने जनता की शैक्षिक और स्वास्थ्य-विषयक स्थिति के सुदृढ़ीकरण को लगातार प्राथमिकता दी है। चूँकि भारत ज्ञान की अग्रणी अर्थव्यवस्थायों में से एक के रूप में उभरने की स्थिति में है, अत: शिक्षा, कौशल विकास एवं स्वास्थ्य जैसे मामले सरकार की प्राथमिकताएँ बने रहेंगे।

सामाजिक क्षेत्रक व्यय की प्रवृत्तियाँ (Trends In Social Sector Expenditure)

स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक अवसंरचना में सरकारी निवेश किसी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण होता है। तथापि वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान केंद्र और राज्यों ने मिलकर सामाजिक सेवाओं पर कुल जीडीपी का करीब 6 प्रतिशत खर्च किया। स्टेट फाइनेन्सेज: अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2016-17 (RBI) से प्राप्त 29 राज्यों के आँकड़ों ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान सामाजिक सेवाओं संबंधी व्यय (GSDP के प्रतिशत के रूप में) में 6.0 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है।

सामान्य सरकार (केंद्र और राज्यों) द्वारा सामाजिक सेवा व्यय की प्रवृत्तियाँ

मद	2014-15	2015-16	2016-17 सं.अ. (Revised Estimate)	2017-18 ब.अ. (Budget Estimate)
				(₹ लाख करोड़)
कुल व्यय	32.85	33.78	40.60	43.96
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	7.68	7.90	9.84	10.94
1. शिक्षा	3.54	3.31	3.95	4.41
2. स्वास्थ्य	1.49	1.52	2.26	2.25
3. अन्य	2.65	3.07	3.63	4.27
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में				
कुल व्यय	26.4	24.7	26.7	26.4
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.2	5.8	6.5	6.6
1. शिक्षा	2.8	2.4	2.6	2.7
2. स्वास्थ्य	1.2	1.1	1.5	1.4
3. अन्य	2.1	2.2	2.4	2.6
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में				
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	23.4	23.4	24.2	24.9
1. शिक्षा	10.8	9.8	9.7	10.0
2. स्वास्थ्य	4.5	4.5	5.6	5.1
3. अन्य	8.1	9.1	8.9	9.7
सामाजिक सेवाओं के प्रतिशत के रूप में				
1. शिक्षा	46.1	41.9	40.2	40.3
2. स्वास्थ्य	19.4	19.2	22.9	20.6
3. अन्य	34.6	38.9	36.9	39.1

स्रोत: *केंद्रीय एवं राज्य सरकारों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के बजट प्रपत्र।*
टिप्पणी: ***1.*** *सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, खेल (क्रीड़ा), कला एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण, श्रम एवं श्रम कल्याण, सामाजिक*

http://t.me/M

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत शामिल नहीं है/हैं?
   (a) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात का निर्धारण करना।
   (b) संबंधित इमारत और अवसंरचना का मार्गनिर्देशन करना।
   (c) बालक-बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधी नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था करना।
   (d) विद्यालय कार्य दिवसों और शिक्षकों के कार्य घंटों से संबंधित मानक तैयार करना।

2. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना निम्नलिखित में से किन मंत्रालयों का सम्मिलित प्रयास है?
   1. महिला और बाल विकास मंत्रालय
   2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
   3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 2 और 3
   (d) 1, 2 और 3

3. हाल ही में सरकार द्वारा किन श्रम संहिताओं, मौजूदा कानूनों तथा केंद्रीय अधिनियमों को युक्तिसंगत बनाने की कोशिश की जा रही है?
   1. मज़दूरी संहिता
   2. औद्योगिक संबंध संहिता
   3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संहिता
   4. सुरक्षा व कार्यदशाएँ संहिता

   निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2 और 4
   (c) केवल 2 और 3
   (d) 1, 2, 3 और 4

4. राजनीति में महिलाएँ 2017 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के संदर्भ में विचार कीजिये:
   1. लोकसभा में 64 महिला संसद सदस्य थीं (542 संसद सदस्यों का 11.8 प्रतिशत)।
   2. राज्यसभा में 27 महिला संसद सदस्य थीं (245 संसद सदस्यों का 11 प्रतिशत)।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

5. समायोजित अशक्तता वाले जीवन वर्षों (DALY) का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
   1. डीएएलवाई किसी विशेष कारण से असामयिक मृत्यु एवं अशक्तता को व्यक्त करता है।
   2. डीएएलवाई दो घटकों जीवन वर्ष हानि (YLL) और अशक्तता के साथ यापित जीवन वर्ष (YLD) से बना है।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. वर्ष 2014 में एंटीमाइक्रोबीयल प्रतिरोधकता को विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में वैश्विक चिंता का विषय बताया गया है।
   2. भारत सहित उन विकासशील देशों में एंटीमाइक्रोबीयल प्रतिरोधकता चिंता का प्रमुख विषय नहीं है जहाँ संक्रामक रोगों का बोझ उच्च तथा स्वास्थ्य देख-रेख व्यय निम्न हो।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. विश्व बैंक के आकलन के अनुसार स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की कमी की लागत भारत की जीडीपी के 6 प्रतिशत से अधिक है।
   2. यूनिसेफ के आकलन के अनुसार ग्रामीण भारत के एक ओडीएफ गाँव में एक परिवार प्रत्येक वर्ष ₹50,000 बचाता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

8. हाल ही में 'द फायनेंशियल एंड इकोनॉमिक इम्पेक्ट ऑफ एसबीएम इन इंडिया (2017)' नामक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की गई?
   (a) यूनिसेफ
   (b) विश्व व्यापार संगठन
   (c) विश्व बैंक
   (d) आई.एम.एफ.

उत्तरमाला

1. (c)	2. (d)	3. (d)	4. (c)	5. (c)
6. (a)	7. (c)	8. (a)		

http://t.me/Md_Ebooks

बजट 2018-2019
(Budget 2018-19)

बजट 2018-19

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को संसद में आम बजट 2018-19 पेश किया।

बजट 2018-19 की मुख्य विशेषताएँ

- बजट में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये परिव्यय का संशोधित अनुमान ₹21.57 लाख करोड़ है जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये बजट का आकलन ₹21.47 लाख करोड़ का था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये ₹24.42 लाख करोड़ के परिव्यय का अनुमान लगाया गया है।
- वित्त मंत्री ने 2018-19 के लिये राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये संशोधित राजकोषीय घाटे का अनुमान ₹5.95 लाख करोड़ का है, जो जीडीपी का 3.5 प्रतिशत है।
- बजट में राष्ट्रपति का वेतन ₹5 लाख, उपराष्ट्रपति का ₹4 लाख और राज्यपाल का ₹3.5 लाख प्रति माह करने का प्रस्ताव किया गया है।
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिये बजट में ₹150 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
- सरकार ने आगामी खरीफ मौसम की सभी अघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, उत्पादन लागत का कम-से-कम डेढ़ गुना करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री के अनुसार रबी की अधिकांश घोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, लागत से डेढ़ गुना तय किया जा चुका है।
- इस बजटीय आवंटन के साथ ही ₹5,000 करोड़ के 'सूक्ष्म सिंचाई कोष', ₹10,881 करोड़ के 'डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना कोष', ₹2,000 करोड़ का 'एग्री बाज़ार अवसंरचना कोष' एवं ₹10,000 करोड़ के 'मत्स्यन एवं एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोष' व 'पशुपालन अवसंरचना विकास कोष' की व्यवस्था की गई है।
- किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने तथा उपभोक्ताओं को कृषि उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये एक नई पहल 'ऑपरेशन ग्रीन' की घोषणा की गई है। इसके लिये बजट में ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- बजट में किसानों को आवश्यकता अनुरूप तय समय पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिये कृषि क्षेत्र के कुल ऋण, जो विगत वर्ष में ₹10 लाख करोड़ था, को इस वर्ष बढ़ाकर ₹11 लाख करोड़ किया गया है। पशुपालन एवं मात्स्यिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा यह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

https://t.me/Md_Ebooks

2018-19 बजट एक नज़र में

	2016-17	2017-18		2018-19
	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियाँ	13,74,203	15,15,771	15,05,428	17,25,738
पूंजी प्राप्तियाँ	6,00,991	6,30,964	7,12,322	7,16,475
कुल प्राप्तियाँ	19,75,194	21,46,735	22,17,750	24,42,213
कुल व्यय	19,75,194	21,46,735	22,17,750	24,42,213
राजस्व घाटा	3,16,381	3,21,163	4,38,877	4,16,034
प्रभावी राजस्व घाटा	1,50,648	1,25,813	2,49,632	2,20,689
राजकोषीय घाटा	5,35,618	5,46,531	5,94,849	6,24,276
प्राथमिक घाटा	54,904	23,453	64,006	48,481

नोट: सभी राशि ₹करोड़ में हैं।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- बजट 2018-19 में सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वर्ष 2017-18 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को कुल ₹51,576 करोड़ का आवंटन किया गया था जबकि इस वर्ष इसका आवंटन बढ़ा कर ₹58,080 करोड़ कर दिया गया है।
- कृषि तथा गैर-कृषि क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिये इस वर्ष बजट में 'राष्ट्रीय बाँस मिशन' का नए रूप में पुनर्गठन कर ₹1290 करोड़ की निधि के साथ संचालित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके माध्यम से लघु उद्योगों की स्थापना व नए रोज़गारों का भी सृजन किया जा सकेगा।

- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में लाने के लिये एक फ्लैगशिप योजना 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण' के नाम से प्रारंभ करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री के अनुसार यह सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की अब तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना है। इसके तहत गरीब और कमज़ोर परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिये प्रति परिवार ₹5 लाख का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की परिकल्पना के अनुसार 1.5 लाख स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। बजट में इसके लिये ₹1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- सरकार ने भी सभी टी.बी. रोगियों को उनके उपचार की अवधि के लिये ₹500 प्रति माह की दर से पोषण सहायता प्रदान करने के लिये अतिरिक्त ₹600 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार देश के मौजूदा ज़िला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की भी स्थापना करेगी।

स्वास्थ्य (Health)



- आयुष्मान भारत पहल के अंतर्गत 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों के ज़रिये व्यापक स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रदान की जाएगी। ये केंद्र गैर-संचारी रोगों के लिये तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं हेतु आवश्यक दवाएँ व नैदानिक उपचार मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे।
- 10 करोड़ गरीब तथा कमज़ोर परिवारों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत द्वितीयक एवं तृतीयक सेवा के अस्पताल में इलाज के लिये प्रति परिवार ₹5 लाख तक का प्रति वर्ष कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- तपेदिक के सभी मरीज़ों के लिये पोषाहार सहायता।
- विद्यमान ज़िला अस्पतालों का उन्नयन करते हुए 24 नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों की स्थापना करना। प्रत्येक तीन संसदीय क्षेत्रों के लिये एक मेडिकल कॉलेज सुनिश्चित किया जाएगा।

बुनियादी ढाँचा और वित्तीय क्षेत्र विकास

वित्त मंत्री ने बुनियादी ढाँचा के विकास को अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बताते हुए समूचे देश को एक नेटवर्क में जोड़ने के लिये ₹50 लाख करोड़ की आवश्यकता बताई है। उन्होंने 2018-19 में बुनियादी ढाँचे पर ₹5.97 लाख करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव दिया है।

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत करीब 35 हज़ार किलोमीटर सड़क के निर्माण के चरण एक को अनुमति दी जा चुकी है और जिसकी अनुमानित लागत ₹5,35,000 करोड़ है।

अवसंरचना (Infrastructure)



- सेला दर्रे के नीचे एक सुरंग का निर्माण किया जाएगा।
- दस प्रमुख पर्यटक स्थलों को प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 100 आदर्श स्मारकों पर पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा।
- बाज़ार से इक्विटी जुटाने के लिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अभिनव मुद्रीकरण संरचना जैसे कि टोल, प्रचालन एवं अंतरण (टीओटी) तथा अवसंरचना निवेश निधि (इन्विट्स) का प्रयोग करेगा।
- एक वर्ष में एक बिलियन यात्राओं की प्रबंध व्यवस्था करने के लिये नेक्स्टजन एयरपोर्ट फॉर भारत (एनएबीएच) निर्माण के अंतर्गत विमानपत्तन क्षमता का विस्तार 5 गुना से अधिक किया जाएगा।
- 'पे ऐज यू यूज' पर टोल प्रणाली की शुरुआत।
- अवसंरचना पर व्यय ₹4.94 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹5.97 लाख करोड़ किया जाएगा।

मध्यम लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोज़गार

बजट में मध्यम लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये बजट में ₹3794 करोड़ प्रदान किये गए हैं। वर्ष 2015 में शुरू की गई मुद्रा योजना के अंतर्गत अभी तक ₹10.38 करोड़ के मुद्रा लोन दिये गए। इनमें से 76 प्रतिशत ऋण खाते महिलाओं के जबकि 50 प्रतिशत से ज़्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये मुद्रा योजना के अंतर्गत ₹3 लाख करोड़ के ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises)



- नकदी प्रवाह की चुनौतियों को आसान करने के लिये ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) शुरू करना।
- सरकार अगले 3 वर्षों में सभी सेक्टरों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों की मज़दूरी का 12 प्रतिशत अंशदान करेगी।
- इस वर्ष 70 लाख औपचारिक रोज़गार सृजित किये जाने हैं।
- वस्त्र सेक्टर के लिये ₹7148 करोड़ का आवंटन बढ़ाया गया।

नीति आयोग की रिपोर्ट
(Reports of Niti Aayog)

नीति आयोग के 3 वर्ष (Three Years of Niti Aayog)

अपनी स्थापना के 3 वर्ष पूरे होने पर नीति आयोग ने अपने नीति-निर्माण कार्य की समीक्षा की है। इसमें आयोग ने नवीन भारत के पुनरुत्थान की दिशा में बनाई गई महत्त्वपूर्ण नीतियों की झलकियाँ प्रस्तुत की हैं।

नई नीति, नई दिशा, नया भारत (Nayi Niti, Nayi Disha, Naya Bharat)

- जनवरी 2015 में स्थापित नीति आयोग भारतीय लोकतंत्र की नवीनतम संस्था है।
- वैसे, योजना आयोग रूपी पुरातन संस्था को प्रतिस्थापित करने वाली इस संस्था का मूल उद्देश्य केंद्रीय योजना-निर्माण की पुरातन शैली को नवाचारी रूप देकर विकास की अवधारणा को नया स्वरूप प्रदान करना है।
- देखा जाए तो इसके अंतर्गत सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण, विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय सहमति विकसित करना, सुधारों को पुनर्परिभाषित करना, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक मुद्दों के समाधान के लिये मंच प्रदान करना और ज्ञान व नवाचार के हब के रूप में कार्य करना शामिल हैं।

मज़बूत राष्ट्र के लिये मज़बूत राज्य – सहयोगी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना (Strong States for A Strong Nation – Promoting Cooperative and Competitive Federalism)

महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन एवं परिणाम के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करना *(Measuring Performance and Ranking States on Outcomes in Critical Sectors)*

- नीति आयोग ने परिमाणों पर ज़ोर देते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा व जल जैसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के लिये सूचकांक जारी किया है ताकि श्रेष्ठ परिणाम पाने के लिये राज्य अच्छी योजनाओं और नवाचारों को साझा करते हुए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें।
- वहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों के प्रदर्शन को मापने व उनकी निगरानी के लिये ज़िला अस्पताल सूचकांक (District Hospital Index–DHI) जारी किया गया है।
- साथ ही, राज्यों में अर्थव्यवस्था, अवसंरचना एवं उपलब्ध सरकारी सेवाओं की प्रगति को डिज़िटली रूप में मापने के लिये नीति आयोग ने डिज़िटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स (Digital Transformation Index–DTI) को भी विकसित किया गया है।

सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल-साथ *(Sustainable Action for Transforming Human Capital–SATH)*

'साथ' का उद्देश्य राज्यों को तकनीकी सहयोग देते हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के संकेतकों में सुधार लाना है। इसके तहत कुछ निश्चित चुनौती वाले मानकों के आधार पर राज्यों को चुना जाता है। तभी तो उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक को जहाँ स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिये चुना गया है, वहीं मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड का चयन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत (Ek Bharat Shreshta Bharat)

देश में 'विविधता में एकता' की अवधारणा को मज़बूत करने के उद्देश्य से दीर्घकालिक रूप में राज्यों के मध्य शिक्षा व संस्कृति के आदान-प्रदान का नवाचारी कदम उठाया गया है। इस विचार को आगे बढ़ाने में उच्चतर शिक्षा विभाग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहल की है। वहीं, संपूर्ण भारतवर्ष से 100 लोकप्रिय संवादयोग्य वाक्यों का चयन कर उन्हें 22 विविध भारतीय भाषाओं में अनूदित कर एक पुस्तक का रूप भी प्रदान किया गया है।

बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये 'राज्यों को विकास सहायता सेवाएँ प्रदान करना' [Development Support Services to State (DSSS) for Development of Infrastracture]

'राज्यों के लिये विकास सहायता सेवाएँ' (Development Support Services to States–DSSS) वास्तव में एक केंद्र-राज्य भागीदारी मॉडल है। इसमें बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र की परियोजनाओं में जोखिम कम करने, संगठनात्मक क्षमता के निर्माण एवं प्रमुख संरचनात्मक मुद्दों की पहचान करने के लिये निजी-सार्वजनिक भागीदारी व्यवस्था स्थापित की गई है।

विनियामक सुधार *(Regulatory Reforms)*

नीति आयोग ने राजस्थान के लिये कानूनों के एकीकरण को अंतिम रूप दिया और जम्मू और कश्मीर एवं महाराष्ट्र के लिये यह कार्य प्रगति पर है।

http://t.me/MD_Ebooks

सतत विकास लक्ष्य
(Sustainable Development Goal)

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) वर्ष 2030 तक, गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिये, एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है जो सबके लिये एक समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व की सृष्टि करेगा– व्यक्तियों, पृथ्वी और समृद्धि के लिये।

17 एसडीजी और 169 लक्ष्य, एक भाग हैं, हमारी दुनिया को बदलने के लिये: सतत विकास के लिये एजेंडा 2030 को, जो सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया, और 1 जनवरी, 2016 को प्रभाव में आया था।

एसडीजी एक अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया से विकसित किये गए हैं, जिसपर विचार-विमर्श करने के लिये इस महत्त्वाकांक्षी एजेंडा को अपनाने के लिये राष्ट्रीय सरकारें और दुनिया भर के लाखों नागरिक एकजुट हुए थे।

SDGs के 17 लक्ष्य (17 Targets of SDGs)

1. सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना
2. भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना
3. स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिये आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना
4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिये आजीवन शिक्षा-प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना
5. लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना
6. सभी के लिये जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना
7. सभी के लिये किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना
8. सभी के लिये सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोज़गार और उचित कार्य को बढ़ावा देना
9. समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना
10. राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानता को कम करना
11. शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाना
12. सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना
13. जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिये तात्कालिक कार्रवाई करना
14. सतत विकास के लिये महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग करना
15. स्थलीय पारिस्थिकी-तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत तरीके से प्रबंधन करना, मरुस्थल-रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना और जैव-विविधता की हानि को रोकना
16. सतत विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना
17. कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना और सतत विकास के लिये वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना

1. सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना

संबंधित तथ्य

- वर्ष 1990 में, पूरी दुनिया में, बुरी तरह से गरीबी (Extreme poverty) की स्थिति में जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या 1.9 बिलियन थी जोकि अब घटकर इसके आधे से भी कम रह गयी है। हालाँकि 836 मिलियन लोग अभी भी बुरी तरह से गरीबी की स्थिति में रहते हैं। विकासशील क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में प्रत्येक पाँचवां व्यक्ति 1.25 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन-यापन कर रहा है।
- बुरी तरह से गरीबी की स्थिति मे जीवन-यापन करने वाले लोगों की बड़ी आबादी दक्षिण एशिया और अफ्रीका के उप-सहारा क्षेत्र में निवास करती हैं।
- प्राय: छोटे, कमज़ोर और संघर्ष प्रभावित (Conflict-affected Countries) देशों में गरीबी की उच्च दर पाई जाती है।
- पूरी दुनिया में, पाँच वर्ष से कम आयु का प्रत्येक चौथे बच्चे की लंबाई उसकी आयु के हिसाब से अपर्याप्त पाई गई है।
- अखिल भारतीय गरीबी प्रमुख गणना अनुपात (All India Poverty Head Count Ratio–PHCR) वर्ष 1990 में 47 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2011-2012 में लगभग आधा होकर 21 प्रतिशत रह गया है।

खंड-6

सरकार की प्रमुख योजनाएँ

प्रमुख योजनाएँ (Major Schemes)

अवसंरचना

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना)
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- उन्नत भारत अभियान
- ग्राम उदय से भारत उदय अभियान

ऊर्जा

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
- एकीकृत ऊर्जा विकास योजना
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
- उजाला योजना
- कुसुम योजना

उद्योग

- मेक इन इंडिया
- स्टैंड-अप इंडिया योजना
- स्टार्टअप इंडिया
- ई-बिज मिशन मोड परियोजना

वित्त

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- अटल पेंशन योजना
- पहल योजना
- संपूर्ण बीमा ग्राम योजना
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- सुकन्या समृद्धि योजना

कृषि

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- परंपरागत कृषि विकास योजना
- ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम)
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

पर्यावरण

- स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)
- स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)
- स्मार्ट गंगा सिटी योजना
- नमामि गंगे परियोजना
- स्मार्ट सिटी मिशन

महिला एवं बाल विकास

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- राष्ट्रीय पोषण मिशन
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

स्वास्थ्य

- मिशन इंद्रधनुष
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना
- सुगम्य भारत अभियान
- आयुष्मान भारत

रोज़गार एवं कौशल विकास

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम
- दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना
- उस्ताद योजना
- प्रधानमंत्री युग योजना-युवा उद्यमिता विकास अभियान
- आजीविका संवर्द्धन के लिये दक्षता/कौशल हासिल करने और ज्ञान बढ़ाने. -संकल्प
- प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना

सूचना प्रौद्योगिकी

- डिजिटल इंडिया
- डिजिटल लॉकर
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

संस्कृति एवं पर्यटन

- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- हृदय योजना
- स्वदेश दर्शन योजना
- प्रसाद योजना : नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिम रेजुवेनेशन एंड स्प्रीचुअल ऑगमेंटेशन

शिक्षा एवं खेल

- नई मंजिल योजना
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना
- खेलो इंडिया
- विद्यांजलि (स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम)
- पढ़ो परदेश योजना
- इम्प्रिंट इंडिया

परिवहन

- भारतमाला परियोजना
- सागरमाला परियोजना
- सेतु भारतम् कार्यक्रम
- उड़ान योजना (उड़े देश का आम नागरिक)

http://t.me/Md_Ebooks

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (Pradhan Mantri Awas Yojana–Urban : PMAY-U)

परिचय (Introduction)

- वर्ष 2022 तक सभी के लिये आवास लक्ष्य को पूरा करने के लिये भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 25 जून, 2015 से इस योजना की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में 2022 तक 2 करोड़ अतिरिक्त घर उपलब्ध करवाना है।
- योजना में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और क्रियान्वयन करने वाली अन्य एजेंसियों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ज़रिये केंद्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
- इस कार्यक्रम के चार प्रमुख घटक हैं– ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना तथा अन्य तीन केंद्र प्रायोजित योजनाएँ– वर्तमान झुग्गियों का उसी स्थान पर निजी सहभागिता के ज़रिये पुनर्वास करना, साझेदारी में किफायती आवास और व्यक्तिगत आवास निर्माण अथवा विस्तार के लिये लाभार्थी आधारित सब्सिडी।
- सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप मिशन में राज्यों को अपने यहाँ मकानों की मांग पूरी करने के लिये चारों अंगों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने की छूट दी गई है। परियोजना का खाका तैयार करने तथा मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मंज़ूरी प्रदान की प्रक्रिया राज्यों के ज़िम्मे कर दी गई है।

लाभार्थी (Beneficiary)

- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
- लाभार्थी परिवार के पास उसके नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसमी रिहाइशी इकाइयों वाला) नहीं होना चाहिये।

कवरेज और अवधि (Coverage and Duration)

500 श्रेणी-I शहरों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जनगणना 2011 के अनुसार सभी 4,041 सांविधिक शहरों को तीन चरणों में कवर किया गया है–

- **चरण-I (अप्रैल 2015-मार्च 2017)**
  राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी इच्छुकता के अनुसार 100 शहरों को कवर करना।
- **चरण-II (अप्रैल 2017-मार्च 2019)**
  अतिरिक्त 200 शहरों को कवर करना।
- **चरण-III (अप्रैल 2019-मार्च 2022)**
  सभी अन्य शहरों को कवर करना।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) (Credit linked Subsidy Scheme)

- प्रधानमंत्री आवास मिशन (शहरी) की दिशा में 2022 तक मिशन के अंतर्गत सबके लिये आवास तथा कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस), लोवर इनकम ग्रुप (एलआईजी) और मिडल इनकम ग्रुप (एमआईजी) हेतु क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की गई है।
- ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिये इसमें 6.5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी तथा एमआईजी जिनकी आय 12 लाख से कम है (एमआईजी-1) के लिये 4 प्रतिशत और 12-18 लाख के आय वर्ग वाले एमआईजी (एमआईजी-2) के लिये सब्सिडी 3 प्रतिशत होगी।
- सब्सिडी की परिगणना हेतु अधिकतम ऋण राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिये 6 लाख, एमआईजी-I के लिये 9 लाख और एमआईजी-2 के लिये 12 लाख होगी।

उद्देश्य (Objective)

- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य घरों का स्वामित्व बढ़ाना और निम्न आय वर्ग वाले तथा मध्यम आय वर्ग वाले लोगों को सस्ते घरों का विकल्प प्रदान करना है। इसके अंतर्गत महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों में आवास स्वामित्व को विकसित करने का प्रयास किया जाना।
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी से किफायती आवास का निर्माण सुनिश्चित करना।
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी।

योजना में नए बदलाव (New Changes in Scheme)

इसमें दो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गए हैं-

- **पहला:** ₹18 लाख तक आय अर्जित करने वाले लोग भी अब इस योजना का फायदा उठा सकेंगे।
- **दूसरा:** कर्ज़ की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 साल किया गया जिससे लाभार्थी को प्रत्येक माह ₹2200 कम जमा करने होंगे।

वितरण	ईडब्ल्यूएस	एलआईजी	एमआईजी-I	एमआईजी-II
वार्षिक आय	₹ 3 लाख	₹ 6 लाख	₹ 12 लाख	₹ 18 लाख
अधिकतम कर्ज की अवधि	20 वर्ष	20 वर्ष	20 वर्ष	20 वर्ष
योजना के तहत कर्ज पाने की योग्यता	₹ 6 लाख	₹ 6 लाख	₹ 9 लाख	₹ 12 लाख
मौजूदा औसत ब्याज दर	9 प्रतिशत	9 प्रतिशत	9 प्रतिशत	9 प्रतिशत
ब्याज सब्सिडी दर	6.5 प्रतिशत	6.5 प्रतिशत	4 प्रतिशत	3 प्रतिशत

मिशन की अवधि एवं कवरेज (Duration of Mission & Coverage)	• स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि पाँच वर्ष (वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20) तक है। इसके पश्चात् इस मिशन को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए जारी रखा जा सकता है। • स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 100 शहरों को कवर करते हुए उनको स्मार्ट सिटी के अनुरूप रूपांतरित किया जा रहा है।
वित्तपोषण (Funding)	• स्मार्ट सिटी मिशन को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। • केंद्र सरकार द्वारा इस मिशन को पाँच वर्षों में ₹48000 करोड़ करीब प्रति वर्ष प्रति शहर ₹100 करोड़ औसतन वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। • इतनी ही राशि का योगदान, समान आधार पर, राज्य, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा किया जाएगा। • इस प्रकार, स्मार्ट सिटी विकास के लिये लगभग ₹1 लाख करोड़ की सरकार/यूएलबी निधियाँ उपलब्ध होगी। • प्रत्येक स्मार्ट-सिटी प्रस्ताव की परियोजना लागत, महत्त्वाकांक्षा के स्तर, मॉडल, निष्पादन और पुनर्भुगतान की क्षमता के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। • स्मार्ट सिटी में कई परियोजनाओं एवं स्कीमों का कार्यान्वयन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर भी किया जा सकता है।
रणनीति (Strategy)	स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र आधारित विकास के कार्यनीतिक घटक नगर सुधार (रेट्रोफिटिंग), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) और नगर विस्तार (हरित क्षेत्र का विकास) के अतिरिक्त पैन सिटी प्रयास जिसमें शहर के बड़े भागों को कवर करते हुए सुव्यवस्थित समाधान (स्मार्ट सॉल्यूशन) लागू किया जाता है। • रेट्रोफिटिंग को वर्तमान निर्मित क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के उद्देश्यों की पुष्टि के लिये, अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ, योजना में शुरू किया जाएगा, जिससे वर्तमान क्षेत्र को अधिक सक्षम और रहने योग्य बनाया जा सके। रेट्रोफिटिंग में, शहर द्वारा नागरिकों के परामर्श से 500 एकड़ से अधिक के क्षेत्र को चिह्नित किया जाएगा। चिह्नित क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सेवाओं के वर्तमान स्तर और निवासियों के विज़न के आधार पर शहर को स्मार्ट बनाने के लिये शहर कार्य नीति तैयार करेगें। • पुनर्विकास से वर्तमान निर्मित वातावरण का प्रतिस्थापन किया जाएगा और मिश्रित भू-प्रयोग और संवर्धित घनत्त्व के प्रयोग द्वारा संवर्धित अवसंरचना के साथ नये ले-आउट को सह-सृजन समर्थ बनाया जाएगा। पुनर्विकास में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा नागरिकों के साथ परामर्श से 50 एकड़ से अधिक के क्षेत्र का पता लगाने की कल्पना की गई है। • हरित क्षेत्र विकास नवीकृत योजना, योजना वित्तपोषण और योजना कार्यान्वयन साधनों (जैसे- लैंड पूलिंग/भूमिपुनर्गठन) का प्रयोग करते हुए पूर्व में खाली पड़े क्षेत्र (250 एकड़ से अधिक) में सुव्यवस्थित समाधानों को आरंभ किया जाएगा और साथ ही किफायती आवासों का प्रावधान विशेषकर गरीबों के लिये भी किया जाएगा। शहरों के आस-पास के हरित क्षेत्रों का विकास बढ़ रही आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये अपेक्षित है। • पैन-सिटी विकास में वर्तमान शहर-व्यापी अवसंरचना में चुनिंदा सुव्यवस्थित समाधानों के प्रयोग की कल्पना की गई है। स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग में प्रौद्योगिकी, सूचना और डाटा शामिल है, जो अवसंरचना और सेवा को उत्तम बनाएंगे। पैन-सिटी प्रदान किया जाना एक अतिरिक्त विशेषता है। • पूर्वोतर और हिमालयी राज्यों के लिये, विकास के लिये प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी वैकल्पिक मॉडल रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास अथवा हरित क्षेत्र विकास के लिये निर्धारित क्षेत्र का आधा होगा।

महिला एवं बाल विकास (Women and Child Development)

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao, Beti Padhao Scheme)	
परिचय (Introduction)	• भारत सरकार ने 2014-15 के बजटीय भाषण में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के घोषणा की थी। • इस योजना के माध्यम से अल्प बाल लिंगानुपात में सुधार लाने, बालिकाओं की शिक्षा के महत्त्व को बढ़ाने तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और विधानों के गठन द्वारा बालिकाओं को शिक्षित करने के लाभ से लोगों को अवगत कराना है। • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस योजना की नोडल एजेंसी है। • बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय सहयोगी संस्थाएँ हैं।

कार्यान्वयन प्रारूप (Implementation Format)	• ये योजनाएँ 'राष्ट्रीय गुणवत्ता अश्योरेंस फ्रेमवर्क' तथा 'राष्ट्रीय दक्षता अर्हता फ्रेमवर्क' के केंद्र एवं राज्य सरकारों की दक्षता/कौशल विकास योजनाओं के सापेक्ष इनके वैश्वीकरण को सहायता प्रदान करेगी और इस प्रकार दक्षता/कौशल, विषयवस्तु एवं उत्पाद के मानकीकरण को सुनिश्चित किया जाएगा। • संकल्प में प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्त्ता अकादमियों के स्वत: प्रसूत मॉडलों की स्थापना पर विचार किया गया है। ये योजनाएँ दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों में ही प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये ऐसे संस्थानों को गति प्रदान करेगी, जिससे अपेक्षित बदलाव आ सकेंगे। • इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य दक्षता विकास मिशनों की स्थापना और राज्यों को ज़िला एवं राज्य स्तरीय दक्षता/कौशल विकास योजनाओं के लिये राज्यों को आगे आने की अनुमति देकर तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने सहित संस्थागत सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने के लिये दक्षता योजना के अत्यधिक विकेंद्रीयकरण पर ज़ोर दिया गया है।
संभावित परिणाम (Expected Outcome)	ये योजनाएँ कौशल विकास प्रणाली को अनुकूल बनाएंगी और उद्योगों को दक्षता प्राप्त कार्य दल की सतत आपूर्ति द्वारा देश के 'ईज ऑफ डूइंग' बिजनेस में वृद्धि करेगी। बेहतर उद्योग संबंध और गुणवत्ता विश्वास के माध्यम से ये योजनाएँ दक्षता विकास कार्यक्रमों के प्रति आकांक्षाओं के महत्त्व के दिशा में भी काम करेगी।

प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana)

परिचय (Introduction)	प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) नियोक्ताओं को प्रोत्साहित एवं नए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विकसित की गई हैं, जिसमें भारत सरकार नए रोज़गार के लिये नियोक्ता को ईपीएफ अंशदान का 8.33 प्रतिशत भुगतान करेगी। इस योजना का दोहरा लाभ है, जहाँ एक तरफ नियोक्ता को प्रतिष्ठान में श्रमिकों के रोज़गार का आधार बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों को एक बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिष्ठानों में रोज़गार मिलेगा और इसका एक प्रत्यक्ष लाभ यह भी है कि इन कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध होंगे।
प्रमुख विशेषताएँ (Main Highlights)	• प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹15,000 प्रति माह से कम आय अर्जित करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। • ईपीएफओ में पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान लाभ उठाने के लिये आवेदन कर सकते हैं। प्रतिष्ठानों के पास श्रम सुविधा पोर्टल के तहत आवंटित श्रम पहचान संख्या (Labour Rentification Number) होना चाहिये। • कर्मचारियों के पास आधार नबंर से जुड़ा एक वैद्य यूनिवर्सल अकाउंट नबंर (Universal Account Number) होना चाहिये। • यह योजना आगामी 3 वर्षों की अवधि वित्तीय वर्ष 2019-20 तक जारी रहेगी। अगले 3 वर्षों तक नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के ईपीएफ में किये जाने वाले 8.33 प्रतिशत अंशदान का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। • गारमेंट (कपड़ा/परिधान) सेक्टर के लिये सरकार नए रोज़गार के लिये 8.33 + 3.67 ईपीएफ अंशदान वहन करेगी। इस योजना का क्रियान्वयन श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिये पीएमआरपीवाई पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)

डिज़िटल इंडिया (Digital India)

परिचय (Introduction)	• डिज़िटल इंडिया कार्यक्रम, भारत को डिज़िटल सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिये है। • डिज़िटल इंडिया की प्रकृति रूपांतरकारी है तथा इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी सेवाएँ नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हो और सार्वजनिक जवाबदेहिता सुनिश्चित हो। • ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाने के लिये और सरकार की समकालिक और समन्वित भागीदारी द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिये सुशासन लाने के लिये उद्देश्य से इस कार्यक्रम के अधीन विभिन्न पहलों को शामिल किया गया है। • ध्यातव्य है कि डिज़िटल इंडिया कार्यक्रम के लिये वर्ष 2018-19 बजटीय आवंटन दोगुना करते हुए ₹3073 करोड़ की घोषणा की गई है।

कार्यान्वयन (Implementation)	● यह मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की पहल है। शोध एवं अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिये एक आईआईएसी व 16 आईआईटी इस कार्यक्रम में सहभागी है। इसके तहत भारत सराकर के 25 मंत्रालयों, परिषदों और विभागों ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ● 'इम्प्रिंट इंडिया' योजना के तहत एक अंतर मंत्रालीय समूह को एकल खिड़की तंत्र के तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। यह प्रमुख अनुसंधानों द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान प्रस्तावों को चयनित करने के उपरांत उनके लिये कोष की स्वीकृति प्रदान करेगा। ● अंतर मंत्रालीय समूह में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सदस्य सम्मिलित होगें।
विशिष्ट विषय (Specific Theme)	● 'इम्प्रिंट इंडिया' इन विषयों में शोध एवं अनुसंधान कार्य करेगा। ये सभी दस विषय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं (IITs) तथा भाारतीय विज्ञान संस्थाओं (IISc) द्वारा संचालित किये जाएंगे– ◆ स्वास्थ्य की देखभाल (Healthcare) – आईआईटी खड़गपुर ◆ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) – आईआईटी खड़गपुर ◆ अग्रिम सामग्री (Advanced Materials) – आईआईटी कानपुर ◆ जल संसाधन एवं नदी प्रणालियाँ (Water Resources and River Systems)– आईआईटी कानपुर ◆ सतत पर्यावास (Sustainable Habitat) – आईआईटी रूड़की ◆ सुरक्षा एवं रक्षा (Security and Defence) – आईआईटी मद्रास ◆ विनिर्माण (Manufacturing) – आईआईटी मद्रास ◆ नैनो प्रौद्योगिकी हार्डवेयर (Nanotechnology Hardware) – आईआईटी बॉम्बे ◆ पर्यावरण विज्ञान और जलवायु परिवर्तन (Environmental Science and Climate Change) – आईआईएससी बंगलुरू ◆ ऊर्जा (Energy) – आईआईटी बॉम्बे
उद्देश्य (Objective)	● देश में नवाचार के लिये आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करना। ● पहचाने गए क्षेत्रों में प्रत्यक्ष वैज्ञानिक अनुसंधान। ● उपरोक्त क्षेत्रों में अनुसधांन के लिये उचित/पर्याप्त कोष की आपूर्ति सुनिश्चित करना। ● इन अनुसंधानों के परिणाम का ग्रामीण व शहरी क्षेत्र पर प्रभाव का आकलन करना। ● तकनीकी संस्थाओं को उन क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिये प्रोत्साहित करना, जिसमें देश दूसरे देशों की तकनीकी पर निर्भर करता है।

http://t.

परिवहन (Transportation)

भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana)	
परिचय (Introduction)	● भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, जो देश में माल और यात्री आवागमन पर ध्यान केंद्रित करता है। ● इस परियोजना का कार्यान्वयन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा किया जा रहा है।
समयावधि (Duration)	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण को 5 वर्षों की अवधि 2017-18 से 2021-22 तक मंजूरी दी है।
प्रमुख चुनौती तंत्र (Grand challenge mechanism)	● भारतमाला परियोजना के तहत प्रमुख चुनौती तंत्र के लिये 10 प्रतिशत फंड आवंटन के लिये रखा जाता है तथा MoRTH मानदंडों के अनुसार राज्य सरकारें समय पर और पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराएंगी। ● प्रमुख चुनौती तंत्र के तहत अधिकतम 100 किमी. की दो सड़कों को किसी राज्य विशेष को एक वित्तीय वर्ष में अनुमति नहीं दी जाएगी। ● राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी प्राथमिकता के आधार पर सड़कों की अंतिम सूची दें, प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में भारतमाला परियोजना में इन्हें शामिल किया जाएगा। ● यदि किसी राज्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार होने के समय भूमि का 50 प्रतिशत अर्जित किया है तो ऐसी परियोजना को फास्ट ट्रेक मोड में रखा जाएगा और MoRTH राज्य को द्वितीय पुष्टीकरण भेजेगा। ● सफल बोलियों (Bidding) से उन परियोजनाओं को चुना जाना है जहाँ 90 प्रतिशत जमीन पहले से ही परियोजना के रूप में अधिग्रहित किये जा चुके हैं।

42. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. विद्यांजलि योजना के अंतर्गत अलग-अलग पृष्ठभूमि और सेवाओं का अनुभव रखने वाले लोग इस कार्यक्रम से जुड़कर बच्चों के साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं।
2. विद्यांजलि योजना पूर्णत: सेवाभाव को ध्यान में रखकर बनाई गयी है इसके लिये कोई आर्थिक भुगतान नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

43. 'पढ़ो परदेश' योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन असत्य है?
(a) इस योजना के अंतर्गत विदेश में उच्च शिक्षा के लिये दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
(b) इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' द्वारा किया जा रहा है।
(c) इसके तहत यदि कोई छात्र बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देता है या उसे शैक्षिक या अनुशासनात्मक आधार पर निष्कासित कर दिया जाता है तो उसे ब्याज में छूट नहीं दी जाएगी।
(d) यदि कोई लाभार्थी भारतीय नागरिकता छोड़ देता है तो उसे भी प्राप्त राशि पर ब्याज दर में छूट नहीं दी जाएगी।

44. 'अटल पेंशन योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. यह स्वैच्छिक आवधिक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है।
2. इस योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है।
3. इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹ 1000 से लेकर ₹ 5000 तक का मासिक पेंशन मिलता हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

45. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के अंतर्गत लघु, सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों को कम लागत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
2. 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत मुहैया कराये जाने वाले ऋणों को राशि के आधार पर शिशु, किशोर व तरुण ऋण योजना में वर्गीकृत किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

46. 'सुकन्या समृद्धि योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं हेतु बचत के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाक घर या अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है।
2. इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को टैक्स से छूट मिलती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

47. 'इंप्रिंट इंडिया' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. यह कार्यक्रम देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध व अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देता है।
2. इस योजना का कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशन में किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

48. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. भारतमाला परियोजना विभिन्न राजमार्गों व बंदरगाहों से संलग्न सड़कों आदि के विकास से संबंधित परियोजना है।
2. भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण को 5 वर्षों की अवधि 2017-18 से 2021-22 तक मंजूरी दी है।
3. इस परियोजना का कार्यान्वयन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

49. 'सागरमाला परियोजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. इसके अंतर्गत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और नये बंदरगाहों का विकास किया जाना है।
2. इसका उद्देश्य कंटेनर के आयात-निर्यात में समय और लागत को कम करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

50. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. 'सेतु भारतम् कार्यक्रम' के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा हेतु पुल निर्माण किया जाना है।
2. 'सेतु भारतम् कार्यक्रम' का मुख्य उद्देश्य 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरमाला

1. (a)	2. (a)	3. (d)	4. (c)	5. (b)
6. (d)	7. (d)	8. (d)	9. (c)	10. (a)
11. (c)	12. (a)	13. (c)	14. (b)	15. (d)
16. (c)	17. (d)	18. (c)	19. (b)	20. (c)
21. (d)	22. (c)	23. (b)	24. (a)	25. (d)
26. (c)	27. (c)	28. (d)	29. (d)	30. (a)
31. (d)	32. (d)	33. (c)	34. (d)	35. (c)
36. (a)	37. (d)	38. (c)	39. (c)	40. (d)
41. (c)	42. (c)	43. (b)	44. (d)	45. (c)
46. (c)	47. (d)	48. (d)	49. (c)	50. (d)

http://t.me/Md_Ebooks

दृष्टि The Vision

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
Distance Learning Programme

उपलब्ध

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 33 बुकलेट्स दी जाएंगी

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(33 बुकलेट्स) ₹10,500/-

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 25 बुकलेट्स दी जाएंगी

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(25 बुकलेट्स) ₹10,000/-

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 36 बुकलेट्स दी जाएंगी

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(28 + 8 बुकलेट्स)

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)	(28 Booklets) ₹10,000/-
सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)	(8 Booklets) ₹2,500/-
सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)	(28+8 Booklets) ₹11,000/-

Available

For UPSC Civil Services Exam (Prelims & Mains) – 2018

Self Learning Modules

Students may opt for following modules

- General Studies (Prelims)
- General Studies (Mains)
- General Studies (Prelims & Mains)

Dispatch Schedule

Prelims Module (GS + CSAT)

- Packet 1 *(4 Booklets)* 25 Dec. 2017
- Packet 2 *(5 Booklets)* 25 Jan. 2018
- Packet 3 *(6 Booklets)* 25 Feb. 2018
- Packet 4 *(5 Booklets)* 25 Mar. 2018

Mains Module

- Packet 1 *(4 Booklets)* 5 May 2018
- Packet 2 *(5 Booklets)* 5 Jun. 2018
- Packet 3 *(4 Booklets)* 5 Jul. 2018
- Packet 4 *(4 Booklets)* 5 Aug. 2018

General Studies

Prelims (17 GS + 3 CSAT Booklets)	₹8000/-
Mains (17 Booklets)	₹7000/-
Prelims + Mains (37 Booklets)	₹13500/-

Invitation Offer

- *Free Subscription of Online Test Series for Prelims 2018 worth ₹6,000*
- *Free Drishti Current Affairs Today Magazine with every dispatch*
- *Dedicated e-mail support for query resolution*

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें
8130392354, 8130392356, 87501-87501, 011-47532596

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें



641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-936314-9-2

मूल्य : ₹ 260